सुविचार

सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि रोज़ किए गए छोटे-छोटे प्रयासों से मिलती है। इसलिए हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और कभी हार न मानें।

प्रथम न्यूज़

PRATHAM NEWS राष्ट्रीय हिंदी दैनिक

Website: www.prathamnews.in email:- dainikprathamnews@gmail.com

Pratham News @dainikprathamnews

स्मृति मंधाना- शेफाली वर्मा की जो है परेशानी, वही है टीम इंडिया की सबसे बड़ी मुश्किल ...

» पृष्ठ 7 पर

जालंधर, वर्ष: 16 अंक : 153 | दिनांक : वीरवार, 04 जून 2026 | सम्पादक : विवेक धीर | सम्पर्कः | 97796-00900 | पन्ने- 8 | मूल्यः ₹ 2.00/- | RNI No I PUNHIN/2010/36540

दिल्ली में आग का कहर : रेस्टोरेंट में 21 लोगों की दर्दनाक मौत

मालवीय नगर के लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में देर रात लगी आग, कई लोग गंभीर रूप से झुलसे, अस्पतालों में उपचार जारी

- 37 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया
- जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को दो-दो लाख

» प्रथम न्यूज । नई दिल्ली

03 जून (एएम नाथ)

दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके मालवीय नगर स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के समय रेस्टोरेंट में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आग लगने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों में जान बचाने के लिए भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को दो-दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस बिल्डिंग में आग लगी वह 6 मंजिल की है। सुबह 8.51 बजे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में आग भड़की थी। जब वहां का कांच फोड़ा गया तो बेसमेंट की तरफ आग फेल गई। यहां फ्लोरिस स्टे होटल संचालित होता था।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत एवं बचाव अभियान के दौरान 37 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट या किसी तकनीकी खराबी के कारण लगने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।

अधिकारियों का कहना है कि रेस्टोरेंट में सुरक्षा मानकों के पालन और अग्निशमन व्यवस्था की भी जांच की जाएगी। घटना ने राजधानी में सार्वजनिक स्थलों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बिल्डिंग से नीचे कूदे लोग

रेस्टोरेंट बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में चल रहा था, जहां आग लगने के बाद बिल्डिंग में तेजी से फैली और पूरी इमारत को चपेट में ले लिया। आग का विकराल रूप देख कई लोग जान बचाने के लिए बिल्डिंग से नीचे कूद गए।

अग्निकांड पर पीएम मोदी और सीएम रेखा गुप्ता ने जताया शोक

मालवीय नगर स्थित रेस्टोरेंट में हुए भीषण अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए आर्थिक सहायता की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को दो-दो लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी घटना पर शोक जताते हुए घायलों के बेहतर उपचार और हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं।

मृतकों में कई विदेशी नागरिक

दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के मुताबिक, सुबह 8.50 बजे आग लगने की सूचना मिली थी।

बिल्डिंग से अब तक 37 लोगों को बचाया जा चुका है। बेसमेंट से भी 6 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। मृतकों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

संक्षिप्त न्यूज

हवाई जहाज का ईंधन होगा सस्ता

केंद्र सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये के फंड को दी मंजूरी

नई दिल्ली (ब्यूरो)- केंद्र सरकार ने एविएशन फ्यूल यानी हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाली ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के फंड की मंजूरी दी है। सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष की वजह से एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत 2.5 गुना बढ़ गई है।

गौरतलब है कि मार्च 2026 में 60.5 रुपये प्रति लीटर से मई 2026 में 142 रुपये प्रति लीटर तक कीमतों में उछाल आई है। केंद्र ने घरेलू ऑपरेशन के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत 75.6 रुपये प्रति लीटर तय की है। फ्यूल की कीमतें एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्ट का लगभग 40 परसेंट हिस्सा है। कीमतों में बढ़ोतरी ने एयरलाइंस और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर बहुत बुरा असर डाला है। सूचना मंत्री ने कहा कि सरकार के इस बड़े फैसले के बहुत फायदे हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच जंग के बाद दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल और हवाई ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। ईरान की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट बंद करने के बाद क्रूड ऑयल की आवाजाही बंद हो गई है और कीमतों में बढ़ोतरी हुई।

कर्नाटक के नए CM बने डीके शिवकुमार, हाथ में संविधान की कॉपी लेकर ली शपथ

भुवनेश्वर (ब्यूरो)- कर्नाटक को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। डीके शिवकुमार ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डीके को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनका शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन स्थित ग्लास में हुआ। शपथ के दौरान डीके शिवकुमार ने एक हाथ में संविधान की कॉपी रखी थी। डीके के शपथ ग्रहण में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांदी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और केरल के सीएम वीडी सतीशन भी मौजूद रहे।

पंजाब सरकार का निजी स्कूलों पर शिकंजा

निजी स्कूल लौटाएंगे 3 साल में वसूली गई अतिरिक्त फीस : मान

पंजाब में फीस बढ़ोतरी पर सख्ती, अब 5त्न से ज्यादा नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक, किताब-यूनिफॉर्म खरीद में भी नहीं चलेगी दबंगई

» प्रथम न्यूज । चंडीगढ़

03 जून (एएम नाथ)

पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा फीस में की जा रही मनमानी पर बड़ा कदम उठाते हुए सख्त कानून लाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में अब कोई भी निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेगा। सरकार ने फीस वृद्धि की अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत तय करने का फैसला किया है। इसके साथ ही पिछले तीन वर्षों में निर्धारित सीमा से अधिक फीस वसूलने वाले स्कूलों को अतिरिक्त राशि अभिभावकों को लौटानी होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार जल्द ही इस संबंध में अध्यादेश जारी करेगी, जिसके बाद इसे विधानसभा के मानसून सत्र में कानून का रूप दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यह देश के सबसे सख्त फीस नियमन कानूनों में से एक होगा। नए नियम सभी निजी स्कूलों पर लागू होंगे, चाहे वे राष्ट्रीय स्तर के हों या अंतरराष्ट्रीय बोर्ड से संबद्ध।

सरकार ने केवल फीस वृद्धि पर ही नहीं, बल्कि किताबों और यूनिफॉर्म की खरीद को लेकर होने वाली कथित मनमानी पर भी रोक लगाने का फैसला किया है। अब किसी भी स्कूल को अभिभावकों पर किसी विशेष दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाने की अनुमति नहीं होगी। इससे अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फीस बढ़ोतरी से जुड़ी अब तक प्राप्त सभी शिकायतों की जांच कराई जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक निजी स्कूल का वार्षिक ऑडिट अनिवार्य किया जाएगा, ताकि वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे और अभिभावकों के हितों की रक्षा हो सके। मान ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान फीस वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने से कई स्कूलों को मनमानी करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही बढ़ेगी और अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।

का मानना है कि इस फैसले से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और निजी स्कूलों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

अमरनाथ यात्रा 2026

हेलीकॉप्टर सेवा फिर बंद, सुरक्षा के चलते लिया गया बड़ा फैसला

» प्रथम न्यूज । नई दिल्ली

03 जून (एएम नाथ)

अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को इस साल भी हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए लगातार दूसरे वर्ष हेलीकॉप्टर संचालन की अनुमति नहीं दी है। इस फैसले से सुरक्षा एजेंसियों को राहत मिली है।

वहीं कई श्रद्धालु निराश भी हैं। खासकर बुजुर्ग, दिव्यांग और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को इससे परेशानी हो सकती है। अमरनाथ यात्रा देश की प्रमुख धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु दक्षिण कश्मीर में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यात्रा के लिए मुख्य रूप से पहलगाम और बालटाल मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है।

बुजुर्गों के लिए काफी मददगार थी हेलीकॉप्टर सेवा

पिछले वर्षों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग करते रहे हैं। इससे यात्रा का समय कम लगता था। शारीरिक मेहनत भी कम करनी पड़ती थी। बुजुर्गों और बीमार यात्रियों के लिए यह सुविधा काफी मददगार मानी जाती थी।

लेकिन हाल के वर्षों में सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा के दौरान हवाई गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना शुरू किया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यात्रा के समय हेलीकॉप्टरों की नियमित उड़ान से सुरक्षा प्रबंधन प्रभावित हो सकता है।

होर्मुज से तेल की टेंशन दूर !

वेनेजुएला से बड़ी डील के आसार, रूस-खाड़ी देशों का मोहताज नहीं रहेगा भारत

» प्रथम न्यूज । नई दिल्ली

03 जून (एएम नाथ)

भारत की पेट्रोल और डीजल की टेंशन आने वाले दिनों में दूर हो सकती है। दुनिया के सबसे बड़े तेल के खजाने वाले देश से अगर डील फाइनल हो गई, तो रूस और खाड़ी देशों पर भारत को मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज भारत दौरे पर आ रही हैं। ऊर्जा और निवेश के क्षेत्र में भारत वेनेजुएला का एक अहम साझेदार है। होर्मुज संकट के दौरान भारत, वेनेजुएला के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते होने के आसार हैं। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष का वैश्विक तेल और सप्?लाई चेन पर लगातार प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में भारत अपने तेज आयातक देशों की लिस्ट में और नाम जोड़ने में जुटा हुआ है। इसी बीच, तेल समृद्ध देश वेनेजुएला की राष्ट्रपति की यात्रा हो रही है। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज, जिन्होंने अमेरिका द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कब्जे में लेने के बाद सत्ता संभाली, 3 से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगी।

दुनिया के सबसे बड़े तेल के खजाने वाले देश से डील के आसार

वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब होर्मुज की नाकाबंदी, जिसने वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा कर दिया, अभी भी जारी है और मोदी सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय भी लोगों को सुझाए हैं। भारत ने अपने आयात में विविधता लाने के प्रयास के तहत वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, वेनेजुएला की राष?ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा में भाग लेंगी, जिसमें भारत-वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा में आगे सहयोग के रास्ते तलाशे जाएंगे।

भारत वेनेजुएला के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अंतरिम राष्ट्रपति के साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था एवं वित्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना एवं परिवहन सहित कई मंत्री होंगे। हाल के महीनों में, भारत वेनेजुएला से तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, मई 2026 तक भारत ने प्रतिदिन 427,000 बैरल तेल खरीदा है, जो दक्षिण अमेरिकी देश से अमेरिका की खरीद के बाद दूसरे स्थान पर है। भारतीय निजी तेल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी हाल के महीनों में वेनेजुएला में कच्चे तेल के तीन सबसे बड़े खरीदारों में अपना स्थान बनाया है।

BCCI की बड़ी बैठक आज

छिन जाएगी सूर्यकुमार यादव की कप्तानी!

» प्रथम न्यूज । नई दिल्ली

03 जून (ब्यूरो)

वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव के हाथों अब टी-20 टीम की कमान नहीं होगी।

सूत्रों के मुताबिक भारत के आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया को एक नया कप्तान मिलेगा। बीसीसीआई की एपेक्स कमिटी की बैठक में आज ये फ़ैसला लिया जाना है। इसी बैठक में और भी बड़े फ़ैसले लिए जाने की उम्मीद है। मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर और चयन समीति आने वाले शनिवार को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का चुनाव करने वाले हैं। एशियन गेम्स के 30 मेंबर के स्क्वाड से सूर्या पहले ही बाहर हैं जबकि वैभव सूर्यवंशी इसका हिस्सा बनाये गये हैं।

टीम इंडिया के विश्व विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी से छुट्टी होने वाली है। भारतीय टीम 6 से 20 जून तक अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक टेस्ट और 3 वनडे मैच की सीरीज़ खेलेगी। इसके बाद भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी। फिर सितंबर में एशियन गेम्स भी है।

खो गई सूर्या की चमक

फिर हफ़्ते भर के अंदर ही भारतीय टीम इसी दौरान 26 जून से आयरलैंड के ख़िलाफ़ 2 टी-20 मैचों की सीरीज़ और फिर 1 जुलाई से इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 5 टी-20 मैचों की सीरीज़ में उतरेगी।

सितंबर अक्टूबर में टीम इंडिया को जापान में टी-20 फॉर्मेट के लिए भी मैदान पर उतरना है। गुरुवार को बीसीसीआई की एपेक्स कमिटी की बैठक में कप्तान सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से मुक्ति दे दी जाएगी। उनके टी-20 टीम में बने रहने पर भी बात होने की बातें की जा रही हैं।

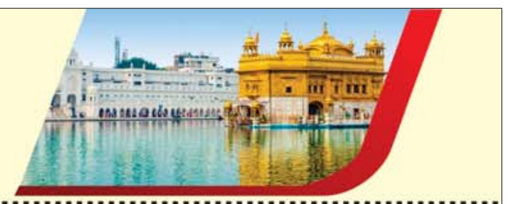

संक्षिप्त न्यूज

विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कैरियर मार्गदर्शन कैंप आयोजित, कैरियर काउंसलर ने दिए सफलता के मंत्र

गुरदासपुर (संदीप सन्नी) – विद्यार्थियों को सुनहरे भविष्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला गाइडेंस काउंसलर मुकेश वर्मा ने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिब्बड़ और खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कादियां का विशेष दौरा किया। इस दौरान उनके साथ गाइडेंस काउंसलर हरदीप सिंह सैनी भी उपस्थित रहे।

विद्यार्थियों से संवाद करते हुए जिला गाइडेंस काउंसलर मुकेश वर्मा ने कहा कि सपनों को साकार करने के लिए सही मार्गदर्शन, आत्मविश्वास और समय पर लिया गया फैसला बहुत जरूरी है। उन्होंने 12वीं के बाद उपलब्ध विभिन्न कैरियर के अवसरों, प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रोफेशनल व तकनीकी कोर्सों और रोजगारोन्मुखी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने स्कूलों में स्थापित गाइडेंस कॉर्नर का निरीक्षण भी किया और वहां नियमित रूप से नई जानकारी अपडेट करने का सुझाव दिया।

इस अवसर पर प्रिंसिपल डॉ. शालिनी दत्ता ने विद्यार्थियों को अनुशासन और कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित किया। अंत में स्कूल प्रबंधकों द्वारा जिला गाइडेंस काउंसलर मुकेश वर्मा को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर वाइस प्रिंसिपल परमिंदर कौर, हेडमास्टर परमजीत सिंह, गाइडेंस शिक्षक विनोद शर्मा, रेणू और कमल सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित थे।

पुलिस ने 7 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार

गुरदासपुर(संदीप सन्नी) – थाना सदर गुरदासपुर की पुलिस ने सुखदेव सिंह नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7 ग्राम हेरोइन बरामद की है। आरोपी के खिलाफ थाना सदर गुरदासपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

मोदी सरकार और रवनीत बिट्टू के खिलाफ बेगमपुरा टाइगर फोर्स का प्रदर्शन, पुतला फूंका

होशियारपुर (तरसेम दीवाना)– बेगमपुरा टाइगर फोर्स के चेयरमैन तरसेम दीवाना और राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मपाल साहनेवाल के दिशा-निर्देशों पर फोर्स के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों तथा भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक, बस स्टैंड होशियारपुर के निकट आयोजित प्रदर्शन के दौरान मोदी सरकार और रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला फूंका गया।

प्रदर्शन की अगुवाई पंजाब अध्यक्ष बीरपाल ठरोली, दोआबा प्रदेश अध्यक्ष नेकू अजनोहा, जिला अध्यक्ष हैप्पी फतेहगढ़ और ब्लॉक अध्यक्ष बंटी हरियाणा ने की। नेताओं ने आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडरों की लगातार बढ़ती कीमतों ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। फोर्स के नेताओं ने भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा अनुसूचित जाति समाज के प्रति कथित रूप से की गई टिप्पणी की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग की भावनाओं को आहत करने वाली भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया और दलित समाज के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर उचित कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में फोर्स के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे।

हिमाचल एंट्री टैक्स के विरोध में निहंगों का ऐलान

पंजाब सीमा पर शुरू हुई 'खालसा टैक्स' वसूली

एंट्री टैक्स विवाद ने लिया नया मोड़, निहंगों ने लगाया 'खालसा एंट्री कर'

पंजाब-हिमाचल सीमा पर निहंगों का विरोध प्रदर्शन, हाईवे जाम की भी चेतावनी

» प्रथम न्यूज । पठानकोट

03 जून (ब्यूरो)

हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स को लेकर चल रहा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। किरतपुर साहिब-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिमाचल सरकार द्वारा लागू किए गए एंट्री टैक्स के विरोध में निहंग संगठन तरना दल ने बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब-हिमाचल सीमा पर 'खालसा एंट्री टैक्स' की वसूली शुरू कर दी है। संगठन का कहना है कि यह कदम हिमाचल सरकार की कर नीति के विरोध स्वरूप उठाया गया है।

जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार द्वारा किसी प्रकार का पंजाब एंट्री टैक्स लागू किए जाने से पहले ही निहंग सिंह संगठन ने पंजाब की सीमा के भीतर, विशेष रूप से मोड़ा क्षेत्र में 'खालसा एंट्री टैक्स' लगाने की घोषणा कर दी। इसके बाद बुधवार से वाहनों से शुल्क वसूला जाना शुरू कर दिया गया।

तरना दल के निहंग अच्छर सिंह ने बताया कि कार और अन्य छोटी गाड़ियों से 100 रुपये, छोटे कमर्शियल वाहनों से 200 रुपये तथा बड़ी गाड़ियों से 300 से 500 रुपये तक की राशि ली जा रही है। उन्होंने कहा कि यह वसूली प्रतीकात्मक विरोध का हिस्सा है और इसका उद्देश्य हिमाचल सरकार के एंट्री टैक्स के खिलाफ आवाज उठाना है।

निहंग संगठन ने आंदोलन को और तेज करने के संकेत भी दिए हैं। इसके तहत दोपहर तीन बजे तक मोड़ा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाने की घोषणा की गई है। इस ऐलान के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है।

एंट्री टैक्स को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब दोनों राज्यों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। आने वाले दिनों में सरकार और प्रदर्शनकारियों के रुख पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

नशा तस्करों पर गुरदासपुर पुलिस का शिकंजा; भारी मात्रा में हेरोइन, नशीली गोलियां और अवैध शराब बरामद

गुरदासपुर (संदीप सन्नी) – विभिन्न थानों की पुलिस टीमों ने मुस्तैदी दिखाते हुए अलग-अलग तारीखों में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और अवैध शराब बरामद की है। पुलिस द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई के दौरान अलग-अलग मामलों में भारी सफलता हाथ लगी :

हेरोइन और नशीली गोलियां बरामद : पुलिस ने विभिन्न नाकाबंदी और चेकिंग के दौरान लकी, मेजर सिंह, सुनील, हरप्रीत सिंह, गगन कुमार, दिनेश कुमार, साहिल कुमार, अनिकेत, रजनीश अत्तरी, सन्नी और राहुल भट्टी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 71 ग्राम 480 मिलीग्राम हेरोइन और प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद कीं। इसके अतिरिक्त थाना धारीवाल की पुलिस ने किशोरी मसीह को 50 नशीली गोलियों के साथ दबोचा।

भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त : आबकारी एक्ट के उल्लंघन मामले में कार्रवाई करते हुए थाना धारीवाल की पुलिस ने जसपिंदर सिंह को 7500 एमएल अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया।

वहीं, थाना दीनानगर की पुलिस ने दो अलग-अलग मुकदमों में दो महिलाओं को काबू कर उनके कब्जे से कुल 54,000 एमएल अवैध शराब बरामद करने में सफलता हासिल की।

प्रधानमंत्री योजना ने बदली लाखों रेहड़ी-पटरी वालों की जिंदगी : हरविंदर संधू

-अमृतसर में 56.49 करोड़ की राशि लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी है।

» प्रथम न्यूज । अमृतसर

03 जून (साहिब दयाल)

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना अमृतसर जिले के रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। भाजपा जिलाध्यक्ष हरविंदर सिंह संधू ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई इस योजना ने छोटे कारोबारियों को बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराकर उनके व्यवसाय को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संधु ने कहा कि अमृतसर जिले में योजना के तहत कुल 47,676 पात्र आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें ?60.17 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जबकि ?56.49 करोड़ की राशि लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा जिले के 16,731 स्ट्रीट वेंडर डिजिटल रूप से सक्रिय हो चुके हैं, जो डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

संधू ने कहा कि जिले के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में अमृतसर नगर निगम सबसे आगे है जहां 43767 पात्र आवेदन, चिरंज पॉइंट 54.92 करोड़ स्वीकृत ऋण तथा 51.51 करोड़ वितरित राशि दर्ज की गई है। इसके अलावा अजनाला नगर परिषद में 798 आवेदन, जंडियाला गुरु नगर परिषद में 1176 आवेदन, मजीठा नगर पंचायत में 609 आवेदन, रईया नगर परिषद में 580 आवेदन, राजा शांति नगर पंचायत में 462 आवेदन तथा रामदास नगर पंचायत में 147 आवेदन दर्ज किए गए हैं। बाबा बकाला अमृतसर कैंट तथा अन्य स्थानीय निकायों में भी इस योजना ने सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरविंदर सिंह संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को 15000, 25000 और 50000 तक के क्रमिक ऋण, समय पर भुगतान पर 7त्न ब्याज सब्सिडी, डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन, क्रेडिट गारंटी सहायता तथा रुपए क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे छोटे विक्रेताओं की साहूकारों पर निर्भरता कम करने और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने का अवसर मिलता है।

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग

मुस्लिम संगठन पंजाब प्रधान एडवोकेट नईम खान ने प्रधानमंत्री के नाम डीसी को दिया ज्ञापन

» प्रथम न्यूज । जालंधर

03 जून (डोगरा)

मुस्लिम संगठन पंजाब के अध्यक्ष एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता नईम खान एडवोकेट ने भारत सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हुए एक ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भेजा है। यह ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर जालंधर वर्जित वालिया के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजने का अनुरोध किया गया है।

ज्ञापन में कहा गया है कि गाय भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक, कृषि, आर्थिक और पर्यावरणीय विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। नईम खान ने कहा कि देश की विविधता और एकता को मजबूत करने के लिए विभिन्न समुदायों के धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान आवश्यक है।

मुस्लिम संगठन पंजाब प्रधान एडवोकेट नईम खान ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया कि गाय करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और उसके प्रति सम्मान राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देता है। संगठन ने कहा कि इस्लाम भी अन्य धर्मों की भावनाओं और मान्यताओं का सम्मान करने तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की शिक्षा देता है। ज्ञापन में गाय के कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया कि दुग्ध उत्पादन के अलावा गोबर और अन्य उत्पाद जैविक खेती, टिकाऊ कृषि और ग्रामीण आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं। नईम खान ने संविधान के अनुच्छेद 48 का हवाला देते हुए कहा कि राज्य को गायों और उनके बछड़ों के संरक्षण तथा नस्ल सुधार के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना संविधान की भावना के अनुरूप होगा। ज्ञापन में सरकार से मांग की गई चंहै कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देकर उसके संरक्षण और सम्मान के लिए आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक कदम उठाए जाएं। नईम खान एडवोकेट ने कहा कि उनकी यह पहल सामाजिक सद्भाव, आपसी सम्मान और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की भावना से प्रेरित है। उन्होंने उपायुक्त जालंधर से ज्ञापन को प्रधानमंत्री तक अग्रेषित करने का अनुरोध किया है।

गांव कीर्तनगढ़ की पंचायत का स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं...

सड़क और नालियों में गंदगी का अंबार, पनप रहे मच्छर, फैल रहीं बीमारियां।

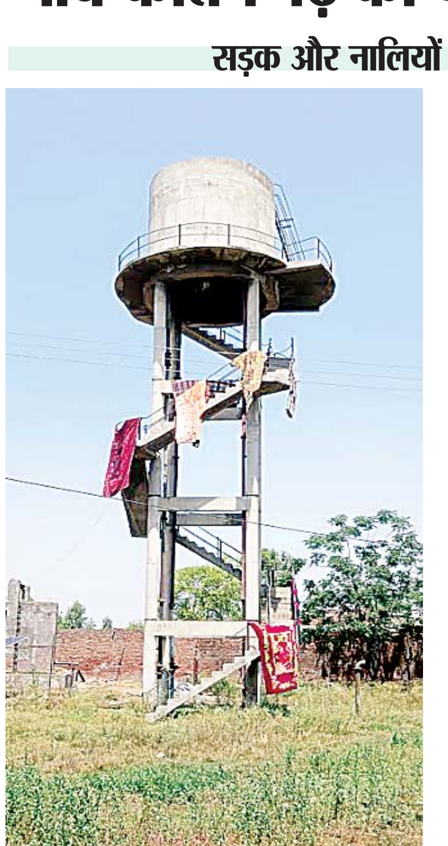

» प्रथम न्यूज । अमृतसर

03 जून (साहिब दयाल)

सरकार से ग्राम पंचायतों को सजाने, संवारने के लिए दिए जाने वाले सरकारी बजट का कितने फीसदी लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है, इसकी असलियत जानना हो तो ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों को देखना चाहिए। ब्लॉक से लेकर जिला दफ्तरों में बैठने वाले अफसर सिर्फ सरकारी बजट खारिज करते हैं, यदि उनसे कराए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता देखना शुरू कर दें तो ग्रामीण पंचायतों को मिले पैसों के दुरुपयोग पर काफी हद तक रोक लग सकती है। गांव कीर्तनगढ़ की ग्राम पंचायत के विकास कार्य देखकर यहां की बदहाली का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। इस गांव में जलनिकासी ना होने से सड़क और गलियों में गंदा पानी भरा रहता है। गांव में कई ऐसे मकान हैं जिनके इर्द-गिर्द गंदा पानी जमा रहता है। शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनाई पेयजल टंकी के नीचे गंदगी की भरमार है। टंकी के नीचे इर्द गिर्द सफाई बिल्कुल नहीं है। स्थानीय लोगों द्वारा कपड़े सुखाने के लिए टंकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नालीयों के पानी की निकासी न होने के कारण पानी सड़क पर फैला हुआ है। गांव के लोग गंदगी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे है। गंदी नालियों और खुले सीवरेज से गंध आने लगी है, मच्छर भी पनप रहे हैं, बीमारियां फैलने का डर है। पंचायत की घोर लापरवाही का खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं।

जिला प्रशासन द्वारा शख्त निर्देश दिए जाते हैं कि सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए पर कुछ ऐसे सरपंच हैं जो स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दे रहे। उन्हें न किसी अधिकारी का भय है ओर न ही सरकार के आदेश की चिंता। ग्रामीणों ने कहा कि उच्च अधिकारियों द्वारा गांव में आकर निरीक्षण करना चाहिए। गुरुद्वारा साहिब के नजदीक रहते लोगों ने बताया कि माथा टेकने जाते उनके बच्चे कई बार गंदी नालियों में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। इस बारे में बीड़ीपीओ बिक्रमजीत सिंह ब्लॉक वेरका ने बताया कि गांव कीर्तनगढ़ के सर्वपक्षीय विकास के लिए 50 लाख रूपए की ग्रांट का एस्टीमेट तैयार करके सरकार को भेजा है, जल्द ही काम शुरू करवाया जाएगा।

नगर कौंसिल चुनाव : चुनाव ऑब्जर्वर कमल कुमार गर्ग ने लिया गुरदासपुर, दीनानगर और कादियां की तैयारियों का जायजा

गुरदासपुर (संदीप सन्नी) – पंजाब राज्य चुनाव आयोग द्वारा गुरदासपुर जिले में होने जा रहे गुरदासपुर, दीनानगर और कादियां नगर कौंसिल चुनावों के लिए कमल कुमार गर्ग को विशेष इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। चुनाव ऑब्जर्वर ने गुरदासपुर पहुंचकर आगामी स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों और व्यवस्थाओं का बारिकी से जायजा लिया।

अपने दौरे के दौरान उन्होंने गुरदासपुर और दीनानगर में चल रही नामांकन प्रक्रिया का विशेष रूप से निरीक्षण किया। जिला प्रशासन द्वारा नामांकन केंद्रों पर उम्मीदवारों की सहूलियत और सहायता के लिए किए गए सुरक्षा व प्रशासनिक प्रबंधों पर उन्होंने पूरी संतुष्टि व्यक्त की।

नियमों का सख्शती से पालन करने और निष्पक्षता पर जोर : अधिकारियों और चुनाव अमले को संबोधित करते हुए चुनाव ऑब्जर्वर कमल कुमार गर्ग ने कहा कि इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों और आदर्श चुनाव आचार संहिता के अनुसार पूरी सख्ती के साथ मुकम्मल करना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि मतदान वाले दिन पोलिंग बूथों पर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे मतदाताओं को अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने दोहराया कि जिले की तीनों नगर कौंसिलों के चुनावों को पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाया जाएगा।

शिकायतों के लिए यहां करें संपर्क : चुनाव ऑब्जर्वर ने आम जनता और उम्मीदवारों की सुविधा के लिए जानकारी साझा करते हुए बताया कि यदि किसी भी नागरिक को चुनाव प्रक्रिया, आचार संहिता के उल्लंघन या किसी अन्य प्रकार की गड़बड़ी से संबंधित कोई शिकायत दर्ज करवानी हो, तो वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित संपर्क माध्यम जारी किए गए हैं।

जीरा विकास परिषद ने गौ सेवा से जुड़ी परियोजनाएं शुरू कीं

» प्रथम न्यूज । जीरा

03 जून (अंग्रेज बराड़)

भारत विकास परिषद से अलग हुए सदस्यों द्वारा गठित नवगठित संगठन जीरा विकास परिषद की पहली बैठक श्री गोपाल कृष्ण गौशाला, न्यू जीरा रोड, जीरा में आयोजित की गई।

बैठक का उद्देश्य सामाजिक सेवा संबंधी कार्यों की शुरुआत से पूर्व ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना था। इस अवसर पर गौशाला में गायों को सवा मणि एवं अन्य सामग्री अर्पित कर सेवा कार्य किया गया। संरक्षक सुखदेव

बिट्टू विज ने कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करना है। उन्होंने बताया कि परिषद आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं शुरू करेगी। महासचिव जगदेव शर्मा ने कहा कि संगठन में प्रत्येक सदस्य को सम्मान दिया जाएगा तथा सामूहिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। अध्यक्ष चरणप्रीत सिंह सोनू, वित्त सचिव पुष्पिंदर सिंह हैप्पी और सह-वित्त सचिव गुरबख्श सिंह विज ने पहली बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त

किया। महिला विंग अध्यक्ष वनिता झांजी ने घोषणा की कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शीघ्र ही एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जाएगा।

बैठक में परिषद के पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला विंग की सदस्यों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सभी ने संगठन को मजबूत बनाकर समाज के हर वर्ग तक सेवा कार्य पहुंचाने का संकल्प लिया।

प्रथम न्यूज
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक

संक्षिप्त न्यूज

नगर परिषद चम्बा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी

चम्बा (एएम नाथ) – उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) प्रियांशु खाती ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद चम्बा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की कार्यवाही, जो 3 जून को निर्धारित की गई थी, हिमाचल प्रदेश नगर परिषद निर्वाचन नियमावली, 2015 के नियम 89 के अंतर्गत आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) पूर्ण न होने तथा अध्यक्ष पद हेतु केवल एक नामांकन पत्र प्राप्त होने के कारण संपन्न नहीं हो सकी।

उन्होंने कहा कि इस कारण निर्वाचन की कार्यवाही को स्थगित करते हुए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है।

उन्होंने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्र 4 जून को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक उपमंडल अधिकारी (नागरिक), चम्बा के कार्यालय में दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा तथा नाम वापसी की प्रक्रिया दोपहर 12:00 बजे से 12:30 बजे तक संपन्न की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इसके उपरांत 4 जून को 1:00 बजे नगर परिषद चम्बा के निर्वाचित सदस्यों की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मतपत्र जारी किए जाएंगे तथा मतदान प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना कर अध्यक्ष पद के निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी।

उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के परिणाम घोषित होने के पश्चात उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की कार्यवाही भी नियमानुसार तत्काल संपन्न करवाई जाएगी।

जिला रोजगार कार्यालय चम्बा में 9 जून को आयोजित किया जाएगा कैंपस इंटरव्यू : जितेंद्र सिंह

चंबा (एएम नाथ)– जिला रोजगार अधिकारी जितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला रोजगार कार्यालय बालु, चंबा में 9 जून को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें टेरियर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल 52 पदों को भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास और ऊंचाई 170 सेमी और इससे अधिक अनिवार्य है, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए स्नातक होना आवश्यक है। दोनों पदों के लिए पुरुष और महिला आवेदकों हेतु आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति लुधियाना और चंडीगढ़ में की जाएगी। सुरक्षा गार्ड पदों के लिए सीटीसी 20,226 रुपये प्रतिमाह तथा कंप्यूटर ऑपरेटर पदों के लिए 27,520 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। चयनित अभ्यर्थियों को वेतन के अतिरिक्त भविष्य निधि (पीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) तथा कंपनी के नियमानुसार अन्य सुविधाओं एवं लाभों का भी प्रावधान रहेगा।

उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए अपने शैक्षिणक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बायोडाटा आदि दस्तावेज लेकर निर्धारित तिथि व स्थानों पर सुबह 11 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित बनाएं।

इंदौरा पंचायत समिति सदस्यों का शपथ ग्रहण 8 जून को

एसडीएम ने जारी किया आदेश

इंदौरा (दिनेश धीमान) कांगड़ा जिला के विकास खंड इंदौरा की पंचायत समिति के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून 2026 (सोमवार) को आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में उपमंडलाधिकारी (ना.) इंदौरा एवं विहित प्राधिकारी डॉ सुरिंदर ठाकुर द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार पंचायत समिति इंदौरा के नवनिर्वाचित सदस्यों को पंचायत समिति हॉल, इंदौरा में सुबह 11-00 बजे गोपनीयता एवं पद की शपथ दिलाई जाएगी। यह प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के प्रावधानों के तहत संपन्न करवाई जाएगी। आदेश में संबंधित सदस्यों को निर्धारित समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शपथ ग्रहण की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। शपथ ग्रहण के बाद पंचायत समिति के कार्यों को लेकर आगे की औपचारिकताएं भी पूरी की जाएंगी।

रेखा ठाकुर का डाक विभाग का आरडी लाइसेंस गुम, क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील

बिलासपुर(जितेंद्र गौतम) उपमंडल झंडुता की ग्राम पंचायत भडोलीकलां के अंतर्गत गांव भडोली खुर्द निवासी रेखा ठाकुर का डाक विभाग का आरडी एजेंसी लाइसेंस कहीं गुम हो गया है। लाइसेंस गुम होने के बाद रेखा ठाकुर ने क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील की है ताकि उनका महत्वपूर्ण दस्तावेज जल्द से जल्द मिल सके।

रेखा ठाकुर ने बताया कि वह डाक विभाग से संबंधित आरडी एजेंसी का कार्य करती हैं और उनका लाइसेंस नंबर 0074701 है। किसी कार्य के दौरान उनका लाइसेंस कहीं गिर गया या खो गया, जिसकी काफी तलाश की गई, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। लाइसेंस गुम होने के कारण उनके दैनिक कार्यों में भी परेशानी उत्पन्न हो रही है।

उन्होंने स्थानीय लोगों से अनुरोध किया है कि यदि किसी व्यक्ति को यह लाइसेंस मिले या उसके संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हो, तो तुरंत उनके मोबाइल नंबर 9805490187 पर संपर्क करें। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके बिना कार्यालयी कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

रेखा ठाकुर ने क्षेत्रवासियों के सहयोग की उम्मीद जताते हुए कहा कि यदि किसी को लाइसेंस मिलता है और वह उसे वापस कर देता है तो वह उसकी सदैव आभारी रहेंगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि मानवता के नाते इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को लौटाने में सहयोग करें।

हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव

अब सभी स्कूलों की परीक्षाएं दिसंबर में : रोहित ठाकुर

» प्रथम न्यूज । शिमला
03 जून (एएम नाथ)

हिमाचल प्रदेश में सभी ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों में बोर्ड कक्षाओं को छोड़कर अन्य कक्षाओं की परीक्षाएं दिसंबर माह में आयोजित होंगी। मौजूदा व्यवस्था के तहत शीतकालीन स्कूलों में परीक्षाएं नवंबर दिसंबर में होती हैं, जबकि ग्रीष्मकालीन स्कूलों में मार्च में परीक्षाएं आयोजित होती हैं। अब एक साथ ही परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बुधवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में राज्य के 148 सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई संबद्धता प्राप्त हो चुकी है। भविष्य में और अधिक विद्यालयों को सीबीएसई पाठ्यक्रम से जोड़ा जाएगा।

कॉलेजों में अब अप्रेंटिस समाहित डिग्री कोर्स के साथ विदेशी भाषा की भी पढ़ाई : सरकार स्नातक डिग्री पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों के लिए अप्रेंटिसशिप समाहित डिग्री कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस पहल के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न उद्योगों के साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा और उन्हें स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। इससे उनके कौशल विकास के साथ रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महाविद्यालय स्तर पर विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की भाषा दक्षता प्राप्त होगी और अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

500 रुपये बढ़ा हुआ मानदेय जारी करने के निर्देश

शिक्षा मंत्री ने कहा कि बजट घोषणा के अनुरूप शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत एसएमसी अध्यापकों, मिड-डे मील कर्मियों, जल वाहकों, कंप्यूटर शिक्षकों और बहु-उद्देशीय कर्मियों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। उन्होंने इसे जारी करने के निर्देश भी बैठक में अधिकारियों को दिए।

10वीं 12वीं रिजल्ट की समीक्षा, शिक्षकों की रुकेगी वेतनवृद्धि

बैठक में 10वीं व 12वीं कक्षा के रिजल्ट की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणामों का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है।

बायोमीट्रिक में हाजरी न लगाने वालों का कटेगा वेतन

बार बार आदेश जारी करने के बाद भी बायोमीट्रिक में हाजिरी न लगाने वालों पर अब कार्रवाई होगी। शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि आदेशों की अनुपालना न होने की स्थिति में वेतन कटौती जैसे कदमों पर भी बल दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभिन्न श्रेणियों के 1,131 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां एलडीआर श्रेणी के माध्यम से की गई हैं।

इसके अतिरिक्त 714 पीजीटी और 102 डीपीई पदों के लिए एलडीआर प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाएगी। कंप्यूटर शिक्षकों के मामलों में आवश्यक नियम संशोधन किए जाएंगे।

उपनिदेशक पद के लिए जल्द होगी डीपीसी

शिक्षा मंत्री ने विभाग को उप निदेशकों की पदोन्नति संबंधी विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला अटॉर्नी के पद सृजित करने संबंधी प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा। वर्ष 2023 और 2025 की आपदाओं से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग और हिमुडा को 19 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

निर्धारित रूट से बाहर चल रही निजी बसों पर कार्रवाई की मांग, स्थानीय लोगों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन

» प्रथम न्यूज । बिलासपुर
03 जून (धर्मपाल)

बिलासपुर से नालागढ़, बद्दी और श्री नैना देवी मार्ग पर संचालित निजी बसों द्वारा निर्धारित रूट का पालन न किए जाने और यात्रियों के साथ कथित दुर्व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में क्षेत्र के लोगों ने उपायुक्त बिलासपुर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई है।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कई निजी बसें अपने निर्धारित रूट पर नहीं चलती हैं, जिससे स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों तथा स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कोठीपुरा, कल्लर, दनोह, जमली, गंबर पुल और बड्डू सहित कई क्षेत्रों के यात्रियों को नियमित परिवहन सुविधा नहीं मिल पा रही है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार कुछ बस चालक और परिचालक यात्रियों को बीच रास्ते में उतार देते हैं तथा दूसरी बसों में बैठने के लिए मजबूर करते हैं। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि कई बार यात्रियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता है। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि इस संबंध में पहले भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तथा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (ऋझह) को शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले का संज्ञान लेते हुए निजी बस संचालकों के खिलाफ जांच और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।

ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि एक सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान नहीं किया गया और नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो क्षेत्रवासी कोठीपुरा फोरलेन चौक पर क्रमिक अनशन शुरू करने को मजबूर होंगे।

स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए तथा निर्धारित रूट से बाहर चलने वाली बसों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। शिव कावड़ संघ अध्यक्ष अरुण सिंह मराठा , गौरी गौ शाला अध्यक्ष पवन शर्मा , स्थानीय लोग , स्थानीय महिला शक्ति , व युवाओं ने ज्ञापन सौंपा द्य ज्ञापन की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, आरटीओ बिलासपुर तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।

शिमला पहाड़ी स्वाद महोत्सव के तहत पाक कला प्रतियोगिता का आईएचएम कुफरी में सफल आयोजन

» प्रथम न्यूज । शिमला
03 जून (बी.शर्मा)

अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव-2026 के तहत आयोजित किए जा रहे शिमला पहाड़ी स्वाद महोत्सव के अंतर्गत पाक कला प्रतियोगिता (Culinary Competition) का आज आईएचएम शिमला (कुफरी) में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता संस्थान के प्रधानाचार्य डॉ. मुकुल डिमरी के मार्गदर्शन एवं संरक्षण में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की समृद्ध पाक विरासत, पारंपरिक व्यंजनों तथा स्थानीय खाद्य संस्कृति को बढ़ावा देना था।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त शिमला सचिन शर्मा रहे। उन्होंने प्रतियोगिता में प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित पाक-कौशल, नवाचार एवं हिमाचली व्यंजनों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं पाक विरासत को व्यापक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

प्रतियोगिता के सफल आयोजन, समन्वय एवं मूल्यांकन कार्य हेतु आईएचएम शिमला की ओर से प्रशांत विजेता, विभागाध्यक्ष तथा यथार्थ चौहान, वरिष्ठ प्रवक्ता को समन्वयक एवं निर्णायक के रूप में नामित किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्णायक मंडल में नंद लाल, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC), शिमला ने भी अपनी विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हुए प्रतियोगिता के निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रतियोगिता में प्रस्तुत किए गए पारंपरिक हिमाचली व्यंजनों, स्थानीय खाद्य संस्कृति तथा प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित पाक-कौशल की निर्णायक मंडल द्वारा विशेष सराहना की गई। निर्णायकों ने स्थानीय सामग्री के प्रभावी उपयोग, व्यंजनों की प्रामाणिकता तथा उनकी उत्कृष्ट प्रस्तुति को हिमाचल प्रदेश की समृद्ध पाक विरासत का सशक्त प्रतिनिधित्व बताया।

30 प्रतिभागियों ने लिया भाग, अगले चरण के लिए 13 प्रतिभागियों का हुआ चयन

प्रतियोगिता में 30 प्रतिभागियों द्वारा स्थानीय एवं पारंपरिक हिमाचली व्यंजनों के साथ-साथ नवाचारपूर्ण पाक-कौशल का प्रदर्शन किया गया, जिसका मूल्यांकन स्वाद, प्रस्तुतीकरण, मौलिकता, स्वच्छता तथा तकनीकी दक्षता के आधार पर किया गया। इनमें से 13 प्रतिभागियों का चयन अगले चरण की प्रतियोगिता के लिए किया गया है, जिनमें 05 स्वयं सहायता समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एक समूह राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तथा 07 ओपन कैटेगरी के हैं। यह चयनित 13 प्रतिभागी 8 से 12 जून तक रानी झांसी पार्क में स्टाल स्थापित करेंगे और इस दौरान आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिसके बाद अंतिम विजेता का चयन किया जाएगा।

मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0 अभियान शुरू, आपसी सहमति से सुलझेंगे लंबित मामले

» प्रथम न्यूज । बिलासपुर
03 जून (जितेंद्र गौतम)

सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर प्रतीक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अदालतों में लंबित मामलों को मध्यस्थता, सुलभ एवं आपसी सहमति से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0 अभियान आरम्भ किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत अदालतों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अदालतों में कई मामले लंबे समय तक लंबित रहते है। इससे दोनों पक्षों का बहुमूल्य समय और धन खर्च होता है। इससे बचने के लिए मध्यस्थता, सुलभ एवं आपसी सहमति एक बहुत ही बेहतर माध्यम हो सकता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई पक्ष इस अभियान के तहत अपने केस जैसे वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस के मामले, दुर्घटनाओं से संबंधित केस, क्रिमिनल कंपाउंडेबल अपराध, बीमा और एलए इत्यादि से संबंधित मामलों का निपटारा करवाना चाहता है तो वह सम्बन्धित अदालत में आवेदन कर सकता है तथा इसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। उन्होंने बताया कि मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0 अभियान के अंतर्गत लंबित मामले को मध्यस्थता से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतें भी लगाई जाती है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर, 2026 को जिला बिलासपुर के सभी न्यायिक परिसरों में लगाई जाएंगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दूरभाष नम्बर 01978-221452 पर संपर्क कर अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन किया जा सकता हैं।

जनगणना-2027 में स्वगणना अपनाएं, 15 जून तक पोर्टल पर स्वयं दर्ज करें जानकारी: राहुल कुमार

बचत भवन बिलासपुर में जनगणना-2027 अभियान का औपचारिक शुभारंभ

» प्रथम न्यूज । बिलासपुर
03 जून (जितेंद्र गौतम)

जिला बिलासपुर में जनगणना-2027 अभियान का औपचारिक शुभारंभ आज उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित बचत भवन में किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत ठाकुर, सहायक आयुक्त राजकुमार तथा जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों ने भी भाग लिया।

इस अवसर पर उपायुक्त राहुल कुमार ने जिला वासियों से भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन संचालित जनगणना-2027 अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए कहा कि नागरिक 01 जून से 15 जून, 2026 तक उपलब्ध स्वगणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) सुविधा का लाभ उठाकर अपनी तथा अपने परिवार की जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

उन्होंने स्वयं भी स्वगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर अभियान की औपचारिक शुरुआत की।

उपायुक्त ने बताया कि स्वगणना के लिए नागरिकीजजचेरूध्ध्मेमणबमदेनेण्हवअण्पदध् पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधा सीमित अवधि के लिए उपलब्ध है और इसके माध्यम से नागरिक बिना किसी मध्यस्थ के अपना संपूर्ण विवरण डिजिटल रूप से दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वगणना से जनगणना प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी तथा आंकड़ों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में भी वृद्धि होगी।

राहुल कुमार ने कहा कि जनगणना-2027 देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है, जो आधुनिक तकनीक के माध्यम से संचालित की जा रही है। यह केवल जनसंख्या की गणना का कार्यक्रम नहीं, बल्कि भविष्य की विकास योजनाओं, नीतियों और संसाधनों के वैज्ञानिक नियोजन का आधार भी है। उन्होंने कहा कि नागरिकों द्वारा दी गई सही और पूर्ण जानकारी ही सरकार को क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं का सटीक आकलन करने में सक्षम बनाती है।

उन्होंने बताया कि जनगणना-2027 दो चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं आवासीय गणना का कार्य 16 जून से 15 जुलाई, 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। उपायुक्त ने बताया कि स्वगणना अवधि समाप्त होने के उपरांत प्रगणक एवं पर्यवेक्षक घर-घर जाकर जानकारी का सत्यापन और संग्रहण करेंगे। जिला बिलासपुर में इस कार्य के लिए लगभग 1130 प्रगणकों की तैनाती की गई है, जो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक परिवार तक पहुंचकर जनगणना संबंधी आंकड़े एकत्र करेंगे। उन्होंने सभी नागरिकों से जनगणना कर्मियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया।

उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि जनगणना के दौरान नागरिकों द्वारा दी गई सही और पूर्ण जानकारी ही भविष्य की विकास योजनाओं का आधार बनती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, आवास, सामाजिक सुरक्षा और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह स्वगणना अथवा प्रगणकों को जानकारी देते समय सही तथ्य उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि सही आंकड़ों से सरकार को क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन करने में सहायता मिलती है, जिससे विकास कार्यों की बेहतर योजना बनाई जा सकती है और योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने भी जिला वासियों, पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों से 15 जून से पूर्व स्वगणना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 16 जून के बाद जब प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे, तब उनके पास भारत सरकार द्वारा जारी अधिकृत पहचान पत्र होगा। नागरिक क्यूआर कोड स्कैन कर उनकी पहचान की पुष्टि कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि किसी भी व्यक्ति को पहचान सत्यापित किए बिना व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान कोई भी प्रगणक या सरकारी कर्मचारी किसी नागरिक से बैंक खाते का विवरण, एटीएम कार्ड नंबर, पासवर्ड, ओटीपी अथवा अन्य वित्तीय जानकारी नहीं मांगेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की जानकारी मांगता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस अथवा जिला प्रशासन को दें। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता और सतर्कता के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी की संभावनाओं को प्रभावी रूप से रोका जा सके।

प्रथम न्यूज

राष्ट्रीय हिंदी दैनिक

हरियाणा न्यूज

Website : www.prathamnews.in

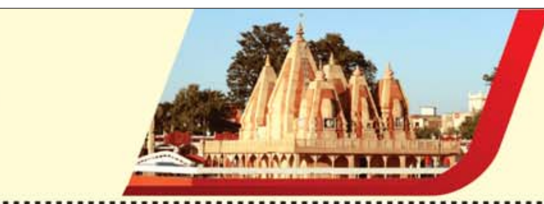

संक्षिप्त न्यूज

युवकों पर जानलेवा हमला करने के मामले में रैकी करने वाला आरोपी थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा काबू

कैथल (कृष्ण गर्ग) : कैथल में जींद रोड के पास युवकों पर जानलेवा हमला करने के मामले में युवकों की रैकी करने वाले आरोपी को थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा काबु कर लिया गया। उक्त मामले में 3 आरोपी पहले ही काबु किए जा चुके है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गांव किठाना निवासी अमन की शिकायत अनुसार वह 24 अप्रैल को अपने दोस्त सिरटा निवासी साहिल और कैथल निवासी मुकेश उर्फ संजू के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर सरकारी हस्पताल कैथल जा रहे थे। जब वे जींद रोड पर टाटा मैट्रो कमर्शियल एजेंसी के नजदीक पहुंचे, तभी एक ग्रे रंग की कार ने उनकी बाइक को पीछे से जानबूझकर टक्कर मार दी, जिससे तीनों सड़क पर गिर गए। तभी कार से उतरे गांव नौच निवासी नितिन अपने साथियों राहुल उर्फ एचपी, रितेश ढांडा, मंजीत उर्फ काला, रमन छौत, अभिषेक उर्फ अभी, सचिन जाखौली व अन्य युवकों के साथ मिलकर हमला कर दिया।

आरोपियों ने उन तीनों पर गंडासी व अन्य हथियारों से वार किए तथा जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई। राहगीरों की मदद से उनको सरकारी अस्पताल कैथल पहुंचाया गया। जिस बारे थाना सिविल लाइन में मामला दर्ज कर लिया गया। मामले की जांच थाना सिविल लाइन पुलिस के एएसआई कुलदीप सिंह द्वारा करते हुए आरोपी गांव कोटड़ा निवासी मोहित सिरोही को काबु कर लिया गया। उक्त मामले में पहले ही आरोपी गुहणा निवासी राहुल उर्फ एचपी, नौच निवासी नितिन तथा गढ़ी निवासी मंजीत को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी मोहित ने युवको की रैकी की गई थी। आरोपी बुधवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिससे पूछताछ की जा रही है।

नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा

कैथल (कृष्ण गर्ग) : एक तरफ जहां पर एसपी मनप्रीत सिंह सूदन के आदेशानुसार जिला पुलिस द्वारा नशा ना करने बारे आमजन को जागरूक किया जा रहा है, वहीं पर पुलिस द्वारा नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इसी मुहिम तहत चौकी किठाना पुलिस द्वारा एक नशा तस्कर को 1.07 किलोग्राम गांजा फूल पत्ती सहित काबू कर लिया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि चौकी किठाना पुलिस प्रभारी पीएसआई रोहित कुमार की टीम सायंकालीन गश्त दौरान गांव कसान अड्डा के पास मौजूद थी। सहयोगी सुत्रो से पुलिस को एक गुप्त जानकारी मिली कि गांव भाणा निवासी गुरमीत उर्फ अमित आस पास के क्षेत्र में नशीला पदार्थ गांजा फूल पत्ती बेचना का काम करता हैं। जो अभी बाइक पर सवार होकर गांव बालू से कसान के रास्ते होते हुए उसके गांव भाणा जायेगा। जिसको नाकाबंदी करके नशीला पदार्थ गांजा फूलपत्ती सहित काबू किया जा सकता। सूचना विश्वसनीय होने कारण पुलिस टीम द्वारा मुस्तैदी का परिचय देते हुए गांव बालू से कसान सड़क पर नाकाबंदी करके कुछ समय बाद बाइक पर सवार आये सन्धिग्ध गुरमीत उर्फ अमित उपरोक्त को काबू कर लिया गया। पुलिस सुचना उपरांत मौके पर पहुंचे एईटीओ कैथल रोहित कुमार के समक्ष नियमानुसार ली गई तलाशी दौरान आरोपी के कब्जे में पॉलीथिन से 1.07 किलोग्राम गांजा फुल पत्ती बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ थाना राजोंद में मामला दर्ज करके मौके पर पहुंचे एसआई दलबीर सिंह द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी बुधवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिससे पूछताछ की जा रही है।

श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विशाल छबील एवं लंगर का आयोजन

चंडीगढ़, 3 जून (पुनीत महाजन)– पांचवें सिख गुरु, श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आज सेक्टर-9 स्थित डीलक्स बिल्डिंग के निकट इंजीनियरिंग विभाग द्वारा श्रद्धा एवं सेवा भावना के साथ पहले प्रसाद देकर उसके बाद विशाल छबील और लंगर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित आसपास के विभिन्न विभागों के स्टाफ सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर गुरु साहिब के प्रति श्रद्धा अर्पित की तथा लंगर ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान ठंडे लस्सी मीठे जल की छबील और चना कुल्चा लगाकर लोगों को गर्मी से राहत प्रदान की गई और सेवा भावना का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जिगना .के. सिंघाडिंया (इलेक्ट्रिकल) संदीप गर्ग एवं इलेक्ट्रिकल विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (XEN) जी.पी. सिंह रहे। तीनों अधिकारियों ने गुरु साहिब के चरणों में नतमस्तक होकर अरदास की तथा लंगर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि श्री गुरु अर्जन देव जी का जीवन त्याग, सेवा, सहनशीलता और मानवता के लिए समर्पण का अनुपम उदाहरण है, जिससे समाज को सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने गुरु साहिब की शिक्षाओं को अपनाने तथा समाज में प्रेम, भाईचारे और सेवा की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अंत में आयोजकों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में स्थापित करने का किया कार्य : नायब सिंह सैनी

प्रदेशाध्यक्ष संगठन और जनता के बीच मजबूत सेतु- मुख्यमंत्री

» प्रथम न्यूज । चंडीगढ़

3 जून (मुकेश डोलिया)

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष संगठन का चेहरा और कार्यकर्ताओं की आशाओं का केंद्र होता है। वह संगठन और जनता के बीच एक मजबूत सेतु होता है और पार्टी की विचारधारा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम होता है। प्रदेशाध्यक्ष का पद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बुधवार को पंचकूला में नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने नव-नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता को हृदय की गहराइयों से बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी ऐसे ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को एक नया नेतृत्व, नई ऊर्जा, नया संकल्प और नई दिशा प्राप्त हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सफल प्रदेशाध्यक्ष केवल संगठन का विस्तार नहीं करता, बल्कि कार्यकर्ताओं के मन को जोड़ता है। वह हर बूथ कार्यकर्ता के योगदान को सम्मान देता है। वह समाज के प्रत्येक वर्ग तक संगठन की पहुंच सुनिश्चित करता है।

नए कार्यकर्ताओं को अवसर एवं नई ऊर्जा को दिशा देता है और संगठन को निरंतर गतिशील बनाए रखता है। नई प्रदेशाध्यक्ष इसी भावना के साथ संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी और उनके नेतृत्व में भाजपा संगठन हरियाणा के हर गांव, वार्ड, बूथ और समाज के प्रत्येक वर्ग तक और अधिक मजबूती के साथ पहुंचेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डा. अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा का संगठन बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त होगा। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। समाज के प्रत्येक वर्ग से संवाद और अधिक मजबूत होगा तथा पार्टी की जनसेवा की परंपरा और अधिक व्यापक रूप से आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा कोई साधारण राजनीतिक दल नहीं है। भाजपा एक विचार, संस्कार और आंदोलन है। राष्ट्र निर्माण का एक सत्त अभियान है। इसमें व्यक्ति नहीं, विचार बड़ा होता है। पद नहीं, जिम्मेदारी बड़ी होती है। भाजपा में सत्ता नहीं, सेवा सर्वोपरि होती है।

भाजपा में कार्यकर्ता सर्वोच्च, संगठन सर्वोपरि और राष्ट्रहित अंतिम लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समारोह केवल दायित्व ग्रहण का कार्यक्रम नहीं है। बल्कि, यह उस विश्वास का प्रतीक है जहां भाजपा में अवसर वंश के आधार पर नहीं, बल्कि क्षमता, समर्पण, परिश्रम और संगठन के प्रति निष्ठा के आधार पर मिलता है। यह केवल संगठन का कार्यक्रम नहीं है। यह एक विचार और नारी शक्ति के सम्मान का उत्सव भी है। भारतीय जनता पार्टी की उस जीवंत परंपरा का उत्सव है, जिसमें कार्यकर्ता सर्वोच्च, संगठन सर्वोपरि है, और राष्ट्रहित अंतिम लक्ष्य है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान ने देश में बेटियों के प्रति सोच बदली। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को आगे बढाने का संकल्प लिया है। भाजपा के 12 साल में लाखों बेटियों को जीवनदान दिया है और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश की महिलाएं सेना के मोर्चे और विज्ञान की प्रयोगशालाओं में अग्रणीय हैं। स्टार्टअप की दुनिया और खेल मैदानों के साथ लोकतंत्र के नेतृत्व में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। हरियाणा इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। नई प्रदेशाध्यक्ष का चयन भी इसी परिवर्तनकारी सोच का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आज बेटियां निर्बल नहीं आत्मनिर्भर है। इसलिए प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेवारी डा. गुप्ता को सौंपी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी मिलकर संकल्प लें और पार्टी संगठन को अधिक मजबूत बनाएं। हर बूथ को सशक्त बनाते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे और हरियाणा के विकास को नई गति देंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार लोकहित में कार्य कर रही है और लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। केन्द्र सरकार ने विकसित भारत 2047 के साथ विकसित हरियाणा का लक्ष्य रखा है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता ने कहा कि पार्टी के लिए कार्यकर्ता होना ही गर्व है।

बूथ से लेकर सभी पदाधिकारियों की महता और जिम्मेदारी होती है कि वे संगठन को आगे बढ़ाते रहें। वे कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार जताया।

समारोह को सम्बोधित करते हुए हरियाणा प्रभारी डा. सतीश पूनिया, केन्द्रीय मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह, सहप्रभारी सुरेन्द्र नागर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिहं, राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़, निवर्तमान अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। समारोह में ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा सहित मंत्री, सांसद, विधायक, बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैन, मेयर एवं बड़ी संख्या में गणमान्य मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में बन रहा नए भारत का स्वरूप

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के इतिहास में दूसरी बार किसी महिला को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह हरियाणा की माताओं, बहनों और बेटियों के सम्मान का क्षण है। यह उस बदलते हुए हरियाणा का प्रतिबिंब है, जहां महिलाएं केवल भागीदारी नहीं कर रहीं, बल्कि नेतृत्व कर रही हैं। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में नए भारत का स्वरूप है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति ने सदैव नारी को शक्ति का स्वरूप माना है। लेकिन वर्षों तक राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने इस स्थिति को बदलते हुए देखा है। प्रधानमंत्री ने केवल नारी सम्मान की बात नहीं की, बल्कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में स्थापित करने का कार्य किया है।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए सही मतदाता सूची जरूरी, नागरिक करें सहयोग : शंभू राठी

एसडीएम शाहाबाद ने पत्रकार वार्ता में एसआईआर बारे दी विस्तृत जानकारी

» प्रथम न्यूज । शाहाबाद

3 जून (बृज मोहन)

शाहाबाद विधानसभा के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं एसडीएम शंभू राठी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को अधिक शुद्ध, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने मतदाताओं से इस महत्वपूर्ण अभियान में सक्रिय सहयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया केवल पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने तथा निर्वाचन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए संचालित की जा रही है।

एसडीएम शंभू राठी उपमंडल कार्यालय शाहाबाद में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में यह विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान के तहत मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन कर उसे शुद्ध किया जाएगा, जिससे प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके और निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता और अधिक मजबूत हो।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सफलता और सशक्त जनभागीदारी के लिए मतदाता सूची का त्रुटिरहित होना अत्यंत आवश्यक है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मृत मतदाताओं के नाम हटाने, दोहरी प्रविष्टियों को समाप्त करने, स्थानांतरित मतदाताओं के रिकॉर्ड को सत्यापित करने तथा नए पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इस पुनरीक्षण के लिए 1 जुलाई, 2026 को अर्हता तिथि निर्धारित की गई है।

एसडीएम शंभू राठी ने कहा कि 14 जून तक बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा उन्हें आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और आवश्यक जानकारी एकत्रित करेंगे। इसी दौरान मतदान केंद्रों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी, ताकि मतदाताओं को मतदान के दौरान बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। जिन बूथों पर 1200 से अधिक मतदाता है उनके रेशनलाइजेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत तैयार ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 21 जुलाई, 2026 को किया जाएगा। इसके पश्चात 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएगी, जिससे पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जा सके तथा सूची में मौजूद त्रुटियों का समयबद्ध समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 72 हजार 945 है। पुनरीक्षण अभियान के तहत 1 लाख 34 हजार 318 मतदाताओं की मैपिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है।

चंडीगढ़ पुलिस ने अंधी लूट की वारदात का किया पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

» प्रथम न्यूज । चंडीगढ़

3 जून (पुनीत महाजन)

चंडीगढ़ पुलिस ने अंधी लूट (ब्लाइंड रॉबरी) के एक मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई एक्टिवा स्कूटी, एक रसोई वाला चाकू, लूटा गया पर्स, नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। इस कार्रवाई को चंडीगढ़ पुलिस की अपराध नियंत्रण दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। महिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कंवरदीप कौर, आईपीएस के निर्देशों तथा पुलिस अधीक्षक (सिटी) के.एम. प्रियंका और एसडीपीओ (साउथ) गुरजीत कौर के मार्गदर्शन में थाना सेक्टर-31 की टीम ने थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरिओम शर्मा के नेतृत्व में इस मामले को सुलझाया। पुलिस ने एफआईआर नंबर 89 दिनांक 2 जून 2026 के तहत दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए विशाल उर्फ अजय (28), विनीत उर्फ बिन्नी (28) और अभि उर्फ लाला उर्फ अवि (25) को गिरफ्तार किया।

शिकायतकर्ता जितेंद्र सिंह, निवासी विकास नगर, मौली जागरां ने पुलिस को बताया कि वह पार्सल डिलीवरी का कार्य करता है। 1 जून को शाम करीब 4–15 बजे हल्लोमाजरा स्थित रविदास मंदिर के पास तीन युवकों ने उसे घेर लिया। एक आरोपी ने चाकू दिखाकर धमकाया, दूसरे ने उसके हाथ पकड़ लिए, जबकि तीसरे ने उसकी जेब से पर्स छीन लिया। पर्स में 3,200 रुपये नकद, आधार कार्ड और पैन कार्ड की प्रति मौजूद थी। पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर मात्र दो दिनों के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान आरोपियों से नकदी, आधार कार्ड की प्रति, पैन कार्ड की प्रति, पीड़ित का पर्स, वारदात में प्रयुक्त चाकू तथा एक्टिवा स्कूटी बरामद की गई। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि तीनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और इनके खिलाफ पहले भी विभिन्न गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है तथा मामले की आगे की जांच जारी है। चंडीगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अभियान लगातार जारी रहेगा।

योग व आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ाकर जीवन शैली को बनाया जा रहा है स्वस्थ : डा. मंजू शर्मा

12 वे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जिले में विभिन्न स्थानों पर आयुर्वेद चिकित्सा शिविर एवं योग प्रोटोकॉल का आयोजन

» प्रथम न्यूज । कुरुक्षेत्र

3 जून (बृज मोहन)

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं महानिदेशक आयुष हरियाणा के निर्देशानुसार तथा जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, कुरुक्षेत्र डॉ मंजू शर्मा के मार्गदर्शन में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जिले के विभिन्न स्थानों पर योग एवं स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डा. मंजू शर्मा ने कहा कि शिविरों एवं योग सत्रों का मुख्य उद्देश्य आमजन में योग एवं आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना रहा। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल धुराला में डॉ. तनवी द्वारा आयुर्वेद संबंधी जानकारी दी गई तथा योग सहायक रजत द्वारा योग प्रोटोकॉल करवाया गया। आंगनवाड़ी यारा में डॉ. संदीप द्वारा दिनचर्या एवं ऋतुचर्या के बारे में बताया गया, फार्मासिस्ट नेहा द्वारा दवाइयां वितरित की गईं तथा दीपक (योग सहायक) द्वारा योगाभ्यास करवाया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल दबखेड़ा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की ओर से आयोजित शिविर में डॉ. मीना द्वारा 69 मरीजों की जांच की गई तथा फार्मासिस्ट सिम्मी लोंगिया द्वारा दवाइयां वितरित की गईं। योग सहायक नरेंद्र कुमार एवं योग इंस्ट्रक्टर संजय कुमार द्वारा योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया गया।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर कलाल माजरा में डॉ. संतोष द्वारा 65 मरीजों की जांच की गई, फार्मासिस्ट धर्मवीर द्वारा दवाइयां वितरित की गईं तथा औषधीय पौधों का वितरण भी किया गया। इस दौरान बेबी दाई भी उपस्थित रहीं तथा अनु (योग सहायक) द्वारा योगाभ्यास करवाया गया। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल बरवा में आयोजित शिविर में डॉ. मोनिका पूनिया द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई, फार्मासिस्ट जसबीर द्वारा दवाइयां वितरित की गईं तथा भीम (योग सहायक) द्वारा योग प्रोटोकॉल कराया गया। आंगनवाड़ी चनार्थल में डॉ. रितु द्वारा महिलाओं को होम्योपैथी के बारे में जागरूक किया गया तथा डिंपल (योग सहायक) द्वारा योगाभ्यास करवाया गया। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीपली में डॉ. सुधीर द्वारा 43 मरीजों की जांच कर दिनचर्या, ऋतुचर्या एवं एचपीवी वैक्सीन के बारे में जानकारी दी गई तथा सविता (योग सहायक) द्वारा योग प्रोटोकॉल कराया गया। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बकली में योग सहायक प्रदीप कुमार द्वारा योगाभ्यास करवाया गया। आंगनवाड़ी मदनपुर में डॉ. प्रणव द्वारा मरीजों की जांच कर आयुर्वेद के बारे में जानकारी दी गई तथा फार्मासिस्ट विजय कुमार द्वारा दवाइयां वितरित की गईं। योग सहायक प्रदीप कुमार द्वारा योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया गया। जिले के मिनी पैराडाइज स्कूल उमरी में हरदीप सिंह, गवर्नमेंट स्कूल लुखी में योग इंस्ट्रक्टर राजी देवर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल मूर्तिजापुर में शिव कुमार, जाट धर्मशाला में बाला देवी, जी.ए.डी. दंगाली में देवेंद्र कुमार, पीएचसी सैना सैंध में संदीप कुमार, गवर्नमेंट कन्या स्कूल शाहाबाद में कर्मवीर, पीएचसी थोल में प्रीतम, जी.ए.डी. सरसा में रामनिवास, पीएचसी खानपुर कोलिया में काजल, गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल थानेसर में दीक्षा, एलएनजेपी हॉस्पिटल में दीक्षा एवं राजीव, आंगनवाड़ी लोहार माजरा में सोनिका एवं स्वाति, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बनी में कमल किशोर तथा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मथाना में अमृत द्वारा योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया गया।

आज का संपादकीय

फिर से ज्ञान का केंद्र बने भोजशाला

धार की परमारवंशकालीन भोजशाला पर आए इंदौर हाई कोर्ट के निर्णय ने गौरवशाली मालवा संस्कृति के ख्यातिप्राप्त राजा भोज की सांस्कृतिक विरासत और उपलब्धियों को याद दिलाने का भी काम किया है। धारा नगरी में विद्वता का सम्मान, कला का उत्कर्ष और संस्कृति का वैभव था। राजा भोज ने जब धारा नगरी को अपनी राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित किया तो उसे केवल शासन का केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान-परंपरा, संस्कृति, पारस्परिक सौहार्द का भव्य नगर बना दिया।

यहां निर्मित भव्य महल, देवालय और शिक्षा केंद्र भारत की समृद्ध सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं। इनमें मां सरस्वती का मंदिर सर्वप्रमुख है। सरस्वती मंदिर के निकट एक विजय-स्तंभ स्थापित कराया गया था। भोपाल के दक्षिण-पूर्व में राजा भोज ने 250 वर्ग मील लंबी भोज सरोवर नामक झील का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया, मेवाड़ के नागोद क्षेत्र में भूदान किया। 1034 में सरस्वती मंदिर परिसर में उन्होंने एक संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कराई, जिसे आज भोजशाला के नाम से जाना जाता है। यह संस्थान नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय की समृद्ध परंपरा के समकक्ष था और लगभग 271 वर्षों तक यह संस्थान विश्वस्तरीय शिक्षा केंद्र के रूप में बहुत प्रतिष्ठित बना रहा।

यह उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भोजशाला परिसर को %सरस्वती लोक% और एक भव्य शोध संस्थान के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। इस परियोजना के तहत भोजशाला परिसर में %राजा भोज शोध संस्थान% स्थापित किया जाएगा, जो राजा भोज की ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। उचित यह होगा कि भोजशाला में अंतरराष्ट्रीय महत्व का ऐसा शैक्षिक संस्थान बने, जो प्राच्य विद्या के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे।

ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए, क्योंकि सम्राट भोज केवल प्रतापी राजा नहीं, बल्कि विद्या, कला, साहित्य और स्थापत्य के महान संरक्षक थे। उनकी राजसभा में विभिन्न कलाओं में निष्णात पांच सौ विद्वानों को आश्रय प्राप्त था। राजा भोज ने धर्म, संस्कृति, खगोल विद्या, वास्तुकला, ज्योतिष, व्याकरण, कोश रचना, काव्य और आयुर्वेद-औषधि जैसे विभिन्न विषयों पर 84 ग्रंथों की रचना की। राजा भोज की काव्यात्मक प्रतिभा भी उच्चकोटि की थी।

इतिहास के पन्नों को पलटने पर ज्ञात होता है कि राजा भोज वीरता और विद्वता के अद्भुत संगम थे। वे रणभूमि में पराक्रमी सम्राट ही नहीं थे, बल्कि भारतीय ज्ञान-परंपरा, संस्कृति और विद्वता के महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल को भारतीय इतिहास में स्वर्णयुग के रूप में याद किया जाता है।

इनमें प्रमुख है उदयपुर-प्रशस्ति अभिलेख। इसमें उनके सफल सैन्य-अभियानों एवं तुर्कों और हूणों के विरुद्ध विजय प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है। उदयपुर प्रशस्ति के साथ-साथ मेरुतुंग कृत प्रबंधचिंतामणि से पता चलता है कि राजा भोज ने अपने समकालीन अनेक शक्तिशाली राज्यों को पराजित कर उदयाचल से अस्ताचल तक शासन किया। इस ग्रंथ में राजा भोज की विद्वता, दानशीलता और उनके द्वारा धारा नगरी में बनवाए गए 104 मंदिरों का उल्लेख मिलता है। वसंत पंचमी के दिन यहां मां वाग्देवी की प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा हुई। वर्तमान में वाग्देवी की प्रतिमा लंदन के एक म्यूजियम में रखी हुई है। आशा है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस प्रतिमा को लंदन से वापस लाने के प्रयास किए जाएंगे और वे सफल भी होंगे।

समकालीन इतिहासकारों और विद्वानों ने राजा भोज को केवल प्रजावत्सल सम्राट ही नहीं, बल्कि श्रेष्ठतम साहित्यकार, कवि-सम्राट और विद्यानुरागी नरेश के रूप में वर्णित किया था। 1055 में जब राजा का देहांत हुआ तो समकालीन विद्वानों ने लिखा, आज राजा भोज के स्वर्ग सिधार जाने से धारा नगरी निराधार हो गई है, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती निराश्रित हो गई हैं और समस्त विद्वतजन आहत हो गए हैं।

शमशानघाट बन गया होटल, लाशों का अंबार

कभी-कभी शब्द कम पड़ जाते हैं। कलम रुक जाती है, क्योंकि जो दर्द कागज पर उतरना है, वह शब्दों की सीमा से बड़ा होता है। 3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर में जो हुआ, उसे सिर्फ 'हादसा' कह देना एक तरह से उस पीड़ा के साथ नाइंसाफी होगी। वह दिन एक होटल-रेस्तरां को शमशानघाट में बदल गया, और कुछ ही मिनटों में हँसी-खुशी से गूँजती जगह लाशों का अंबार बन गई।

उस दिन लोग काम से थककर, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, थोड़ी राहत के लिए आए थे। किसी ने बच्चों के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन रखा था, किसी ने दोस्तों से मिलने का वादा किया था। माहौल सामान्य था-प्लेटों की खनक, बातों की गूँज, वेटर की आवाज़। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह सब एक दहशत में बदल जाएगा।

आग कैसे लगी, यह अभी जांच का विषय है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या रसोई गैस लीकेज इसकी वजह हो सकती है। लेकिन कारण जो भी हो, हकीकत यह है कि आग ने फैलने में एक पल भी नहीं लगाया। धुआँ उठा, बिजली गुल हुई, और चीखों का सैलाब फूट पड़ा। जो लोग दरवाज़े के करीब थे, वे धक्का-मुक्की करके बाहर निकल पाए। जो अंदर फँस गए, वे धुएँ और लपटों के बीच दम तोड़ते रहे।

दमकल विभाग की गाड़ियाँ जब पहुँचीं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग इतनी तेज़ थी कि बचावकर्मियों को अंदर जाने में भी दिक्कत हुई। जब धुआँ थोड़ा छँटा, तो मंजर सामने आया-कुर्सियाँ पिघली हुईं, मेज़ें काली पड़ी हुईं, और फर्श पर जले हुए शव। कुछ शवों के हाथ अभी भी कुर्सियों पर टिके थे, जैसे आखिरी वक्त तक सहारा ढूँढ रहे हों। किसी की नज़र दरवाज़े की तरफ थी, जैसे उम्मीद बाकी थी कि कोई आकर बचा लेगा।

अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 25 से अधिक लोग अस्पताल में हैं, जिनमें से कई की हालत नाज़ुक बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। शव इतने बुरी तरह झुलस चुके हैं कि शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। बाहर खड़े परिजन अपने बच्चों, पतियों, भाइयों के नाम पुकार रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है।

यह दृश्य नया नहीं है। दिल्ली ने पहले भी ऐसे मंज़र देखे हैं-उफरा बाज़ार की फैक्ट्री में आग, अनाज मंडी में धमाका, मुंडका की बिल्डिंग में हादसा। हर बार यही होता है। हादसा होता है, लोग मरते हैं, मीडिया कुछ दिन शोर मचाता है, मुआवजे की घोषणा होती है, जांच बैठती है, और फिर सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। हम शोक मनाते हैं, संवेदना जताते हैं, और फिर अपनी ज़िंदगी में लौट जाते हैं। लेकिन जिनके घर उजड़ते हैं, उनके लिए यह 'फिर से लौटना' मुमकिन नहीं होता।

नरेन्द्र भारती
वरिष्ठ पत्रकार

सवाल यह है कि आखिर हम सीखते क्यों नहीं? नियम तो बने हुए हैं। हर होटल, हर रेस्तरां, हर सार्वजनिक जगह के लिए फायर एनओसी ज़रूरी है। एग्जिट गेट, फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक अलार्म-सब कागज़ों पर दर्ज होते हैं। हकीकत में इनका पालन कितना होता है, यह मालवीय नगर का मंज़र बता देता है। एक छोटी सी चूक, एक लापरवाही, और इक्कीस जिंदगियाँ खत्म।

सबसे दुखद बात यह है कि मरने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जिनका सिस्टम से कोई सीधा लेना-देना नहीं होता। एक वेटर जो दो वक्त की रोटी के लिए काम कर रहा था। एक छात्र जो दोस्तों के साथ खाना खाने आया था। एक परिवार जो महीने में एक बार बाहर खाने का खर्च उठा पाता था। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वे गलत समय पर गलत जगह खड़े थे।

हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया। मुआवजे की घोषणा हुई, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये देने का वादा किया गया। घायलों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन क्या यह काफी है? मुआवजा उस माँ को क्या लौटाएगा जिसका इकलौता बेटा चला गया? उस पत्नी को क्या देगा जिसका सुहाग उजड़ गया? उस बच्चे को क्या मिलेगा जिसने पिता को आखिरी बार भी नहीं देखा?

हमें समझना होगा कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, यह सिस्टम की विफलता है। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक लापरवाह मालिकों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। हम हर बार 'सुरक्षा ऑडिट' की बात करते हैं, लेकिन ऑडिट के नाम पर सिर्फ फाइलें भरी जाती हैं। असल में कभी कोई जाकर नहीं देखता कि एग्जिट गेट पर ताला तो नहीं लगा है, फायर एक्सटिंग्विशर काम करता भी है या नहीं।

मालवीय नगर की यह आग सिर्फ एक इमारत में नहीं लगी। यह हमारे सिस्टम की लापरवाही पर लगी है। यह हमारे उस रवैये पर लगी है जिसमें जान की कीमत से ज्यादा पैसा मायने रखता है। जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक हर होटल, हर रेस्तरां, हर भीड़भाड़ वाली जगह संभावित शमशानघाट बनी रहेगी।

समाज के तौर पर भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। हम अक्सर देखते हैं कि किसी जगह पर भीड़ ज्यादा है, निकास का रास्ता बंद है, फिर भी हम वहीं बैठ जाते हैं। हमें सवाल पूछने चाहिए। हमें यह जानने का हक है कि जहाँ हम खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, वह जगह सुरक्षित है या नहीं। चुप्पी भी एक तरह की सहमति बन जाती है।

आज मालवीय नगर में 21 परिवार टूट गए हैं।

कुछ के घरों में चूल्हा नहीं जलेगा, कुछ के घरों में बच्चों की हँसी हमेशा के लिए बंद हो गई। उनके लिए यह खबर नहीं, उनकी ज़िंदगी है। और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनकी पीड़ा को सिर्फ खबर बनाकर न छोड़ दें।

अब वक्त है कि हम संवेदना से आगे बढ़कर जवाबदेही की बात करें। जांच सिर्फ कागज़ों में न सिमटे। दोषियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि फिर कोई हिम्मत न करे नियमों को ताक पर रखने की। फायर सेफ्टी को लेकर सख्ती हो, नियमित जांच हो, और उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस रद्द हों।

वरना अगली बार भी यही होगा। अगली बार भी कोई और होटल, कोई और रेस्तरां, कोई और बाज़ार शमशानघाट बन जाएगा। और हम फिर से यही शीर्षक छापेंगे-शमशानघाट बन गया होटल, लाशों का अंबार। फिर से मोमबत्ती जलाएंगे, फिर से सोशल मीडिया पर RIP लिखेंगे, और फिर से भूल जाएंगे।

लेकिन जो चले गए, वे नहीं भूलेंगे। उनकी अधूरी साँसें, उनके अधूरे सपने, उनकी माँ की आखिरी चीख-ये सब हवा में तैरते रहेंगे। और हमें याद दिलाते रहेंगे कि एक ज़िंदा समाज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है-जान की कीमत।

अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम फिर से भूल जाएंगे, या इस बार सच में बदलेंगे?

विद्यालयों में विदेशी भाषा शिक्षा का महत्व

आज का युग वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और अंतरराष्ट्रीय संपर्क का युग है। दुनिया पहले की तुलना में कहीं अधिक जुड़ी हुई है। शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को पढ़ना-लिखना सिखाना नहीं है, बल्कि उन्हें वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करना भी है। इस संदर्भ में विद्यालयों में विदेशी भाषाओं का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। अंग्रेज़ी के अतिरिक्त फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चीनी, जापानी, कोरियाई, रूसी तथा अरबी जैसी भाषाओं का ज्ञान विद्यार्थियों को नई संभावनाओं और अवसरों से जोड़ता है। विदेशी भाषा शिक्षा न केवल करियर निर्माण में सहायक है, बल्कि यह बौद्धिक विकास, सांस्कृतिक समझ और वैश्विक दृष्टिकोण के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

निशा कैसर
जर्मन लैंग्वेज प्रशिक्षक
स्प्रिंगडेल स्कूल, अमृतसर

विदेशी भाषा सीखने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह विद्यार्थियों की संचार क्षमता को विस्तृत बनाती है। जब कोई छात्र एक से अधिक भाषाएँ जानता है, तो वह विभिन्न देशों और संस्कृतियों के लोगों के साथ आसानी से संवाद कर सकता है। वर्तमान समय में व्यापार, शिक्षा, विज्ञान, पर्यटन और कूटनीति जैसे क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बहुभाषी व्यक्तियों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। विद्यालय स्तर पर विदेशी भाषा शिक्षा विद्यार्थियों को भविष्य की इन आवश्यकताओं के लिए तैयार करती है।

विदेशी भाषा का अध्ययन मानसिक और बौद्धिक विकास में भी सहायक होता है। अनेक शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि जो विद्यार्थी एक से अधिक भाषाएँ सीखते हैं, उनकी स्मरण शक्ति, समस्या-समाधान क्षमता, रचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल बेहतर होते हैं। भाषा सीखने की प्रक्रिया मस्तिष्क को सक्रिय रखती है और उसे नए ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करती है। इससे विद्यार्थियों की एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। यही कारण है कि कई विकसित देशों की शिक्षा प्रणालियों में विदेशी भाषा शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी विदेशी भाषा शिक्षा का विशेष महत्व है। प्रत्येक भाषा अपने साथ एक संस्कृति, इतिहास, परंपरा और जीवन शैली को लेकर चलती है। जब विद्यार्थी किसी विदेशी भाषा को सीखते हैं, तो वे उस भाषा से जुड़े समाज और संस्कृति को भी समझने लगते हैं। इससे उनमें विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान, सहिष्णुता और संवेदनशीलता विकसित होती है। आज के समय में जब दुनिया विविधताओं से भरी हुई है, तब विभिन्न संस्कृतियों को समझने और स्वीकार करने की क्षमता अत्यंत आवश्यक है। विदेशी भाषा शिक्षा विद्यार्थियों को संकीर्ण सोच से बाहर निकालकर व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है।

विदेशी भाषा का ज्ञान रोजगार और करियर के क्षेत्र में भी अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ ऐसे कर्मचारियों को प्राथमिकता देती हैं जो विभिन्न भाषाओं में संवाद करने में सक्षम हों। पर्यटन, विमानन, होटल प्रबंधन, अनुवाद, दुभाषिया सेवा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी सेवा, पत्रकारिता और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विदेशी भाषा का ज्ञान विशेष महत्व रखता है। यदि विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर से ही विदेशी भाषा सीखने का अवसर मिले, तो वे भविष्य में प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में अधिक सफल हो सकते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी विदेशी भाषाओं का ज्ञान लाभकारी है।

विश्व के अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय विभिन्न देशों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ और अध्ययन के अवसर प्रदान करते हैं। जर्मनी, फ्रांस, जापान, चीन और रूस जैसे देशों में उच्च शिक्षा के लिए स्थानीय भाषा का ज्ञान कई बार आवश्यक होता है। यदि विद्यार्थी विद्यालय स्तर पर ही इन भाषाओं का अध्ययन कर लें, तो उनके लिए विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही वे अंतरराष्ट्रीय शोध और अकादमिक संसाधनों तक भी आसानी से पहुँच बना सकते हैं। तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के युग में विदेशी भाषा शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। दुनिया भर में ज्ञान और नवाचार का आदान-प्रदान विभिन्न भाषाओं के माध्यम से होता है। कई महत्वपूर्ण शोध, तकनीकी दस्तावेज और वैज्ञानिक साहित्य विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध होते हैं। विदेशी भाषा का ज्ञान विद्यार्थियों को इन संसाधनों तक पहुँचने और वैश्विक ज्ञान समुदाय का हिस्सा बनने में सहायता करता है। इससे उनकी सीखने की क्षमता और ज्ञान का दायरा दोनों विस्तृत होते हैं।

भारत जैसे बहुभाषी देश में विदेशी भाषा शिक्षा का महत्व विशेष रूप से देखा जा सकता है। भारत तेजी से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। विदेशी निवेश, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक सहयोग के बढ़ते अवसरों के कारण विदेशी भाषाओं का ज्ञान युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल बनता जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी विद्यार्थियों को बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है। यह नीति विद्यार्थियों में भाषाई विविधता के प्रति सम्मान और विभिन्न भाषाओं के अध्ययन की भावना को बढ़ावा देती है।

हालाँकि विद्यालयों में विदेशी भाषा शिक्षा को लागू करने में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, संसाधनों का अभाव और पाठ्यक्रम पर अतिरिक्त दबाव जैसी समस्याएँ सामने आती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग यह भी मानते हैं कि विदेशी भाषाओं पर अधिक ध्यान देने से मातृभाषा की उपेक्षा हो सकती है। लेकिन वास्तव में विदेशी भाषा शिक्षा का उद्देश्य मातृभाषा को कमजोर करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के ज्ञान और अवसरों का विस्तार करना है। यदि संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए, तो मातृभाषा और विदेशी भाषाओं का अध्ययन साथ-साथ सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

विद्यालयों को विदेशी भाषा शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म, भाषा प्रयोगशालाएँ, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और ऑनलाइन शिक्षण संसाधन विद्यार्थियों के भाषा सीखने के अनुभव को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही भाषा शिक्षा को केवल व्याकरण और पाठ्यपुस्तकों तक सीमित न रखकर संवाद, गतिविधियों और व्यावहारिक अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए।

निष्कर्षत:, विद्यालयों में विदेशी भाषा शिक्षा आज की आवश्यकता बन चुकी है। यह विद्यार्थियों को केवल एक नई भाषा नहीं सिखाती, बल्कि उन्हें वैश्विक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक समझ, बेहतर करियर अवसर और बौद्धिक विकास के साधन प्रदान करती है। वैश्वीकरण के इस युग में विदेशी भाषा का ज्ञान विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करता है। इसलिए विद्यालयों में विदेशी भाषा शिक्षा को प्रोत्साहित करना समय की मांग है, ताकि नई पीढ़ी आत्मविश्वास के साथ विश्व मंच पर अपनी पहचान बना सके।

महंगाई की चौतरफा मार

ईंधन के बढ़ते दामों से बेपटरी हुआ घर का बजट, आम गरीब आदमी और मध्यम वर्ग में त्राहि-त्राहि

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि और उससे पैदा होने वाले महंगाई के संकट को लेकर स्थानीय समाजसेवियों और रेंजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने बढती हुई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में एडवोकेट जनरल कार्यालय के सेवानिवृत्त सुपरिंटेंडेंट एवं जाने-माने समाजसेवी श्री राजबीर सिंह भारतीय की अगुवाई में स्थानीय प्रतिनिधियों ने बढ़ती कीमतों पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है और सरकार से पूछा है कि आखिर जनता कब तक इस महंगाई की मुसीबत को सहेगी

रसोई का बजट बिगड़ा, गृहणियों का जीना मुहाल

प्रेस नोट जारिए समाजसेवी कमलेश देवी और पूजा राय ने कहा कि ईंधन के दाम बढ़ने का सीधा और सबसे घातक असर घर की रसोई पर पड़ रहा है। जो गृहणियां पूरा घर और रसोई चलाने की जिम्मेदारी संभालती हैं, उनके लिए अब घर का मासिक बजट संभालना नामुमकिन होता जा रहा है। दूध, सब्जियां, आटा, दालें और तेल नमक जैसी रोजमर्रा की बेहद जरूरी चीजें तेजी से महंगी हो रही हैं। नमक पर बढे टैक्स पर तो हमने अंग्रेजी हुक्मरान के खिलाफ जन आंदोलन किया तथा अंग्रेजी हुक्मरान को झुकना पड़ गया था। आज तो हमारी अपनी स्वतंत्र भारत की सरकार है।

उन्होंने सरकार से पुरजोर मांग करते हुए कहा -सरकार को तुरंत बढ़ती हुई आवश्यक वस्तुओं और खाद्य पदार्थों पर से टैक्स कम कर देना चाहिए। अगर टैक्स में कटौती नहीं की गई, तो एक मध्यमवर्गीय और गरीब परिवार की गृहणी के लिए अपने घर को ठीक ढंग से चलाना पूरी तरह दूभर हो जाएगा।

परिवहन लागत बढ़ने से आम आदमी बेहाल : सुभाष धीमान

मनीमाजरा ईडब्ल्यूएस रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन श्री सुभाष धीमान और राजबीर सिहँ भारतीय सयुंक्त रुप से बयान में आर्थिक आंकड़ों को सामने रखते हुए कहा कि देश में 70 फीसदी से ज्यादा माल ढुलाई सड़क मार्ग से होती है। ट्रांसपोर्टेशन की कुल लागत का 42 फीसदी हिस्सा सिर्फ ईंधन पर निर्भर करता है। 15 मई के बाद से तेल की कीमतों में जो भारी उछाल आया है, उसने ट्रांसपोर्ट सेक्टर की कमर तोड़ दी है।

जनता पूछे सरकार से सवाल, कब तक सहेगी महंगाई की मार? - राजबीर सिंह भारतीय

श्री सुभाष धीमान और राजबीर सिहँ भारतीय ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा -तेल का रेट बढ़ने से माल ढुलाई (ट्रांसपोर्टेशन) का खर्चा बेतहाशा बढ़ रहा है। इसके कारण हर छोटी से छोटी चीज महंगी हो रही है। आज स्थिति यह है कि देश का आम आदमी और मध्यम वर्ग इस बढ़ती महंगाई के आगे त्राहि-त्राहि कर रहा है, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है।

जनता पूछे सरकार से सवाल कब तक सहेगी ये मार - राजबीर सिंह भारतीय

इस पूरे मुद्दे पर समाज के हर वर्ग की आवाज बुलंद करते हुए श्री राजबीर सिंह भारतीय ने रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (CRISIL) की रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ईंधन में 7.5 रुपये से 10 रुपये तक की यह बढ़ोतरी खुदरा महंगाई को करीब 0.48 फीसदी तक बढ़ा देगी। इसके कारण दूध, फल, चाय, कॉफी और मसाले जैसी चीजें आम जनता की पहुंच से दूर होती जा रही हैं।

उन्होंने सरकार के सामने जनता के ये मुख्य सवाल रखे

1. राहत का रोडमैप क्या है क्या सरकार के पास इस चौतरफा आर्थिक संकट और महंगाई जनित दबाव से आम नागरिकों को बचाने की कोई ठोस योजना है
2. टैक्स कम क्यों नहीं हो रहे जब जनता त्रस्त है, तो केंद्र और राज्य सरकारें ईंधन और खाद्य सामग्री पर टैक्स घटाकर तुरंत राहत क्यों नहीं दे रहीं
3. रोजमर्रा की चीजों पर नियंत्रण कैसे होगा ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ने का खतरा है, इसे रोकने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है
4. कब तक सहेगी जनता महंगाई की मार सरकार के पास आम नागरिकों को इस चौतरफा आर्थिक संकट से बचाने की क्या योजना है
5. राहत कब मिलेगी क्या सरकार टैक्स कम करके या अन्य उपायों से ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास करेगी, ताकि आम आदमी को तुरंत राहत मिल सके

श्री राजबीर सिंह भारतीय, सुभाष धीमान, कमलेश देवी और पूजा राय ने संयुक्त रूप से कहा कि सरकार ने तुरंत बढ़ती कीमतों पर लगाम लगानी चाहिए और टैक्स कम करके आम आदमी को राहत देनी चाहिए, वर्ना तो देश की 80-90व जनता का जीना मुहाल और मुश्किल हो जाएगा।

सुभाष धीमान

संक्षिप्त न्यूज

बैंक व विभाग के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने पर की चर्चा

पट्टा मेहलोग में बैंकर्स समिति की बैठक

पट्टा मेहलोग, 3 जून (तारा) – ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक बुधवार को खंड विकास अधिकारी कार्यालय पट्टा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता यूको बैंक की लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तमन्ना मोदगिल ने की। बैठक के दौरान बैंकिंग योजनाओं, वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, ऋण वितरण तथा सरकार प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही आम जनता तक बैंकिंग सेवाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाने एवं विभिन्न विभागों एवं बैंकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी चर्चा की गई।

बैठक में पट्टा ब्लॉक के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न बैंक शाखाओं के प्रतिनिधियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी पट्टा कुलदीप सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे।

प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार को पूरी तरह नकार दिया, मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर नए चुनाव करवाएं : डॉ. राजीव बिंदल

नाहन (बी. शर्मा)– भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुए पंचायतीराज एवं नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड विजय ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की जनता वर्तमान कांग्रेस सरकार से पूरी तरह निराश और आक्रोशित है। इन चुनाव परिणामों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सीधा और स्पष्ट संदेश दिया है कि जनता अब परिवर्तन चाहती है।

डॉ. बिंदल ने कहा कि प्रदेश का युवा, बेरोजगार, किसान, बागवान, कर्मचारी, व्यापारी, सेवानिवृत्त वर्ग और समाज का हर वर्ग आज कांग्रेस सरकार की नीतियों से परेशान है। यही जनाक्रोश चुनाव परिणामों में दिखाई दिया है। नगर निगम चुनावों में भाजपा ने चार में से तीन नगर निगमों में दो-तिहाई बहुमत के साथ शानदार विजय प्राप्त की, वहीं जिला परिषदों में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने व्यापक जनसमर्थन हासिल कर अपना दबदबा स्थापित किया है।

उन्होंने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह विजय भाजपा की नहीं बल्कि जनविश्वास, जनआक्रोश और जनादेश की विजय है। जनता ने विकास, सुशासन और जवाबदेही के पक्ष में मतदान किया है तथा कांग्रेस सरकार की विफलताओं को नकार दिया है।

डॉ. बिंदल ने सिरमौर जिला का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि जिला परिषद चुनावों में भाजपा ने 17 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। यह पहली बार है जब सिरमौर जिला परिषद में भाजपा को इतनी बड़ी सफलता मिली है। कांग्रेस केवल तीन सीटों तक सिमट गई जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। उन्होंने कहा कि सिरमौर की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह वर्तमान सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के प्रभाव क्षेत्रों में भाजपा की बड़ी जीत इस बात का प्रमाण है कि जनता अब कांग्रेस की राजनीति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिन क्षेत्रों को कांग्रेस अपना मजबूत गढ़ मानती थी, वहां भी जनता ने भाजपा को भारी समर्थन देकर सत्ता के अहंकार को जवाब दिया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था कमजोर हुई है और विकास कार्य ठप पड़े हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हैं, पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त स्टाफ नहीं है, शिक्षा व्यवस्था संकट में है और अनेक संस्थानों पर ताले लगाने की नौबत आ गई है। जनता इन सब परिस्थितियों को देख रही है और उसका असर चुनाव परिणामों में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता से किए गए अपने वादों और गारंटियों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है। महिलाओं, युवाओं, किसानों और कर्मचारियों से किए गए वादे अधूरे हैं। इसी कारण प्रदेश की जनता ने इन चुनावों में कांग्रेस को करारा जवाब दिया है।

डॉ. बिंदल ने कहा कि स्थानीय निकाय और पंचायतीराज चुनावों के परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और अब सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार भी नहीं रखती। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि वे जनभावनाओं का सम्मान करते हुए तत्काल इस्तीफा दें और प्रदेश में नए विधानसभा चुनाव करवाने का मार्ग प्रशस्त करें ताकि जनता अपने मत से नई सरकार का गठन कर सके।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास के लिए प्रदेशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करती है और विकास, सुशासन तथा जनसेवा के संकल्प के साथ आगे भी जनता के बीच कार्य करती रहेगी।

अधिकारी मर्यादाएं न लाँघे, सरकार के इशारे पर जनप्रतिनिधियों को परेशान करना पड़ेगा बहुत महँगा : जयराम ठाकुर

थुनाग में सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद वार्डों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से भेंट कर किया संवाद

» प्रथम न्यूज । मंडी
03 जून (एएम नाथ)

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के इशारे पर कुछ अधिकारी नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्रताड़ित करने के लिए मर्यादाएँ लाँघ रहे हैं। उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिये कि उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इस सरकार के साथ वह अपना भविष्य न जोड़ें। अधिकारी नियम क़ानून के दायरे में रहकर काम करें और जनमत का सम्मान करें। बुधवार को थुनाग में सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद वार्डों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से भेंट एवं संवाद के दौरान उन्होंने यह बातें कहीं। उन्होंने खौली, लंबाथाच, शिल्हीबागी, गत्तू, संगलवाड़ा, खारशी, बागाचनोगी सहित ब्रयोगी, रोड एवं मझोठी के नवनिर्वाचित सदस्यों को उनकी शानदार विजय और नवीन दायित्व के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। इस दौरान करसोग विधानसभा के चारों जिला परिषद वार्डों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की प्रचंड जीत के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों ने विधायक दीप राज की अध्यक्षता में और विकास खंड जंजैहली के भाजपा समर्थित नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों ने भी नेता प्रतिपक्ष से विशेष मुलाकात की।

जयराम ठाकुर ने सभी जनप्रतिनिधियों में जोश भरते हुए कहा कि जनता ने उन पर जो विश्वास व्यक्त किया है, उस पर खरा उतरते हुए वे सभी जनसेवा के प्रति समर्पित भाव से कार्य करेंगे और अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों के सतत, समग्र एवं संतुलित विकास को नई दिशा देकर उन्हें सशक्त व समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे क्योंकि विकसित पंचायत से ही विकसित विधानसभा का सपना साकार होगा।

इस अवसर पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि यह जनादेश वर्तमान सरकार की जनविरोधी नीतियों के प्रति जनता के भारी आक्रोश और भाजपा के प्रति लगातार बढ़ते विश्वास का स्पष्ट प्रमाण है, और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस के कुशासन का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देते हुए उसे कड़ा सबक सिखाएगी। उन्होंने सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को सीधे शब्दों में कड़ा अल्टीमेटम दिया कि जो अधिकारी सरकार के इशारे पर हमारे भाजपा समर्थित जनप्रतिनिधियों को परेशान कर रहे हैं, वे साफ़-साफ़ सुन लें कि यह हरकतें उन्हें बहुत महँगी पड़ेंगी। अधिकारी अपनी मर्यादाएं न लाँघे और इस जनविरोधी सरकार के साथ अपना भविष्य जोड़ने की भूल कतई न करें। उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाते हुए खुलासा किया कि चंबा में भाजपा समर्थित एक प्रतिनिधि के घर पर प्रशासन की टीम भेजकर उनके मकान की पैमाइश करवाई गई और उन्हें डराया-धमकाया गया कि यदि उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दिया तो उनका मकान गिरा दिया जाएगा, जो कि बेहद निंदनीय और अलोकतांत्रिक है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में न आने के कारण मुख्यमंत्री पूरी तरह बौखलाहट में हैं और वे झूठे व गलत आंकड़े पेश कर अपने दिल्ली हाई कमान की नजरों से अपनी राजनीतिक असफलता को छुपाने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि मुख्यमंत्री ने अपनी हार के डर से चुनाव से पहले भी इन चुनावों को टालने का हरसंभव प्रयास किया था क्योंकि उन्हें भली-भांति पता था कि जनता उन्हें नकार चुकी है, और अब परिणाम भाजपा के पक्ष में आने के बाद भी वे अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं तथा आगे भी कई तरह के हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आएँगे। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि जनविरोधी नीतियों के कारण इस मुख्यमंत्री के पैरों तले जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है और जनता ने कांग्रेस के खिलाफ अपना स्पष्ट जनादेश सुना दिया है, जिसे मुख्यमंत्री झूठे आंकड़ों के पीछे नहीं छिपा सकते। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे प्रशासनिक दवाब या धमकियों से बिल्कुल न डरें, निडर होकर जनता की सेवा करें क्योंकि भाजपा पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है और भाजपा के साथ ही उनका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में हर वर्ग ने भाजपा का साथ दिया है क्योंकि इस सरकार ने किसान-बागवान, महिलाओं, बेरोजगारों, कर्मचारी वर्ग और व्यापारियों को बहुत परेशान और निराश किया है। हमने हर मंच पर सरकार की उन गलत नीतियों का विरोध किया है जो जनता के हित में नहीं है। हमारे विरोध करने के तरीके से मुख्यमंत्री और उनके मंत्री असहज हो उठते हैं। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम विपक्ष में हैं और आप हमें जनता की आवाज़ बनने से नहीं रोक सकते। जनता ने भाजपा को अपना समर्थन दिया है तो इससे मुख्यमंत्री को विचलित नहीं होना चाहिए। आप अच्छा करते तो जनता आपके साथ चलती लेकिन जनता ने आपको आपके कारनामों को देखते हुए सबक सिखाया है। अभी तो ये सेमीफाइनल था और आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी।

बाड़ियां पंचायत के आधा दर्जन गांव में पेयजल किल्लत

जोहड़जी स्कीम की पहले स्टेज में पंप खराब आने से आई समस्या

पट्टा मेहलोग, 3 जून (तारा) – विकास खंड पट्टा की बाड़ियां पंचायत के आधा दर्जन गांव में पिछले एक सप्ताह से लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। पचायत के मदफल, सकराला, बरागु, जोहड़ का हाडा, गटीवाला व एखू गांव के जोड़ने वाली लाईन बंद है। जोहड़जी स्कीम की फर्स्ट स्टेज दजेला एक हफ्ते से मोटर पंप खराब है, जिसकी वजह से जनता को पानी की किल्लत है। लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे है। मदफल गांव के राजेंद्र कुमार रघुवंशी, परवीन कुमार, नानकु, गुरुदयाल, सकराला से दया पाल, , जोहड़ का हाडा से पूर्व बीडीसी प्रेम चंद, एखू गांव के राजिंदर कुमार, गटीवाला के मान सिंह, बरागु के पूर्व उप प्रधान नेक राम व शिशुपाल ने जल शक्ति विभाग से आग्रह किया है कि पेयजल किल्लत वाले गांवों को बौनी मदफल बड़ेहरी स्कीम से सप्लाई दी जाए। इस स्कीम से कयाटू में पानी डाला जाए जिससे मदफल, सकराला, बरागु, जोहड़ का हाडा गांवों को भी पानी की सप्लाई सुचारू हो सके। वर्तमान में लोग पानी न आने से बाहरी बहाव का पानी ढो रहे है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात में आगे भी यही दिक्कत रहेगी। बरसात के दौरान खड्ड में पानी आने से पंप खराब होने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने बौणी-बडेहरी स्कीम में जोड़ने की मांग की है। उधर, जलशक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता राहुल अबरोल ने बताया कि यहां पर नया पंप लगाया जा रहा है। बुधवार शाम तक योजना को सुचारू कर दिया जाएगा। वीरवार से भी गांव में पानी छोड़ा जाएगा।

शिमला ग्रीष्मोत्सव में नशा उन्मूलन हेतु थीम आधारित महानाटी MAA का होगा आयोजन

(बी.शर्मा) शिमला: अंतरराष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव-2026 के अंतर्गत समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने तथा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से MAA (Mothers Against Abuse and Addiction)' विषय पर एक विशेष थीम आधारित महानाटी का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 09 जून 2026 को पुलिस सहायता कक्ष के समीप दोपहर 3 बजे से सायं 5 बजे तक किया जाएगा जिसमें शिमला के विभिन्न आईसीडीएस खण्ड से लगभग 250 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भाग लेंगी। उपायुक्त शिमला एवं अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव समिति अनुपम कश्यप ने बताया कि इस अभियान का मूल संदेश मां की ममता, समाज की शक्ति है, जिसके माध्यम से माताओं को नशा मुक्त समाज निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान नशे के खिलाफ जन-

जागरूकता, पारिवारिक मूल्यों की मजबूती तथा बच्चों के सुरक्षित भविष्य के प्रति सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित किया जाएगा। महा-नाटी में यह संदेश दिया जाएगा कि प्रत्येक मां का संकल्प हिंसा और नशे के विरुद्ध आवाज उठाने तथा महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने का है। साथ ही, प्रत्येक मां का यह वचन भी होगा कि वह अपने परिवार और समाज को नशे से दूर रखकर एक स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध समाज के निर्माण में योगदान देगी। कार्यक्रम के माध्यम से सशक्त मां, सुरक्षित बचपन, नशामुक्त समाज और उज्ज्वल भविष्य की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन शिमला तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस विशेष जागरूकता अभियान के दौरान आमजन को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा महिला हेल्पलाइन 181 की सेवाओं के संबंध में भी जानकारी प्रदान की जाएगी।

जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से इस जन-जागरूकता कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाकर नशामुक्त एवं सुरक्षित समाज के निर्माण में सहयोग देने का आह्वान किया है।

कांग्रेस सत्ता का सेमीफाइनल हार चुकी है, अब फाइनल खेलने लायक भी नहीं बची : रणधीर शर्मा

नगर निगमों से जिला परिषद और बीडीसी तक भाजपा की सुनामी, कांग्रेस का प्रदेशभर में हुआ सुपड़ा साफ

» प्रथम न्यूज । शिमला
03 जून (बी.शर्मा)

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनाव परिणामों ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों स्पष्ट कर दी हैं।

जनता ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभूतपूर्व जनादेश देकर यह संकेत दे दिया है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का समय निकट है।

रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार शुरू से इन चुनावों को करवाने से बचती रही। कभी पुनर्गठन का बहाना, कभी रोस्टर का बहाना, कभी डिलिमिटेशन का बहाना और कभी अन्य प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर चुनावों को टालने का प्रयास किया गया। सरकार को पहले से आभास था कि जनता के बीच जाने पर उसे करारी हार का सामना करना पड़ेगा। अंततः न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद चुनाव करवाने पड़े और परिणाम वही आए जिसका अंदेशा कांग्रेस को पहले से था। उन्होंने कहा कि चार नगर निगमों में हुए चुनावों में तीन प्रमुख नगर निगमों मंडी, धर्मशाला और सोलन में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। नगर परिषदों में 22 में से 12 और नगर पंचायतों में 25 में से 18 स्थानों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर कांग्रेस को करारा जवाब दिया है।

रणधीर शर्मा ने कहा कि जिला परिषद चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 250 में से 144 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस मात्र 60 सीटों तक सिमट गई। बिलासपुर में कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई। मुख्यमंत्री के गृह जिले हमीरपुर में कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर रही। कई जिलों में कांग्रेस एक या दो सीटों तक सीमित होकर रह गई। यह परिणाम कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से और निराशा का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति (बीडीसी) चुनावों में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रदेश के 1769 वार्डों में से 1109 वार्डों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 477 तक सिमट गई। प्रधान और उपप्रधान पदों पर भी 65 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधि भाजपा विचारधारा से जुड़े हुए हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि यह केवल चुनावी जीत नहीं है, बल्कि जनता द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ सुनाया गया अविश्वास प्रस्ताव है। जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि वह झूठी गारंटियों, खोखले वादों और घोषणाओं की राजनीति से तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के समय कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 प्रतिमाह, युवाओं को रोजगार, किसानों को समर्थन मूल्य, मुफ्त बिजली और अनेक गारंटियां दी थीं, लेकिन तीन वर्ष बीतने के बाद भी इनमें से अधिकांश वादे धरातल पर नहीं उतर सके। यही कारण है कि नगर निगम चुनावों में मुख्यमंत्री द्वारा किए गए बड़े-बड़े वादों और घोषणाओं पर भी जनता ने विश्वास नहीं किया।

रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री आज भी जनादेश को स्वीकार करने की बजाय बहानेबाजी कर रहे हैं। हार की समीक्षा करने के बजाय भाजपा के नेतृत्व पर टिप्पणी करना उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। भाजपा पूरी तरह एकजुट है और प्रदेशभर में कार्यकर्ताओं की मेहनत तथा जनता के आशीर्वाद के कारण यह विजय संभव हुई है।

उन्होंने कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सरकार के जिम्मेदार लोग हार का कारण आंतरिक कलह और गुटबाजी को बता रहे हैं। कांग्रेस पहले अपना घर संभाले, भाजपा को सलाह देने की आवश्यकता नहीं है।

रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि चुनावों के दौरान कई स्थानों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को प्रशासनिक दबाव, भय और तकनीकी अड़चनों का सामना करना पड़ा, लेकिन जनता ने इन सभी प्रयासों को विफल कर दिया। इसके बावजूद भाजपा ने रिकॉर्ड जीत हासिल की।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों, जिला परिषदों और पंचायत समितियों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव होने हैं। यदि सरकार प्रशासनिक दबाव, प्रलोभन या शक्ति का दुरुपयोग कर जनता के जनादेश को बदलने का प्रयास करती है तो भाजपा इसका लोकतांत्रिक और राजनीतिक स्तर पर पुरजोर विरोध करेगी।

रणधीर शर्मा ने कहा कि यह चुनाव हिमाचल की सत्ता का सेमीफाइनल था और कांग्रेस यह सेमीफाइनल बुरी तरह हार चुकी है। अब स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस फाइनल खेलने की स्थिति में भी नहीं बची है। जनता ने अपना मन बना लिया है और आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना तय कर लिया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि जब जनता ने इतने स्पष्ट रूप से सरकार को नकार दिया है तो नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और विधानसभा चुनावों का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए ताकि प्रदेश को एक नई दिशा और मजबूत नेतृत्व मिल सके।

अंत में रणधीर शर्मा ने प्रदेश की जनता, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं विजयी उम्मीदवारों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा जनता के विश्वास को और मजबूत करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।

स्मृति मंधाना- शेफाली वर्मा की जो है परेशानी, वही है टीम इंडिया की सबसे बड़ी मुश्किल

इंग्लैंड की जमीन पर होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. इस ICC टूर्नामेंट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान का आगाज 14 जून को चिर-प्रतिद्वन्दी पाकिस्तान के खिलाफ करेगी. मगर फिलहाल हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी के लिए समस्या वो नहीं, बल्कि जिसके चलते मुश्किलें बढ़ी दिख रही हैं, वो स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की परेशानी है. स्मृति और शेफाली दोनों भारतीय टीम की ओपनर हैं और परेशानी ये है कि इन दोनों का ही बल्ला टूर्नामेंट के करीब आकर खामोश हो गया है.

इंग्लैंड के खिलाफ नहीं चली पार्टनरशिप

स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के बल्ले की चुप्पी का सबसे ताजा उदाहरण इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई 3 T20 मैचों की सीरीज में देखने को मिला. इस सीरीज के तीनों मैचों में ना शेफाली चलीं और ना मंधाना. पार्टनरशिप तो दूर की बात है, दोनों का इंडिविजुअल प्रदर्शन भी उतना ही बेकार रहा है.

सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में स्मृति और शेफाली के बीच हुई पार्टनरशिप की. पहले T20 में दोनों ने एक भी रन स्कोर बोर्ड पर नहीं जोड़े. दूसरे T20 में 27 रन की पार्टनरशिप दोनों के बीच हुई. वहीं तीसरे और आखिरी T20 में स्मृति-शेफाली ने मिलकर 19 रन स्कोर बोर्ड में जोड़े.

स्मृति-शेफाली का बल्ला खामोश

अब जरा इन दोनों के इंडिविजुअल प्रदर्शन को भी देख लीजिए. इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में स्मृति मंधाना का पहले T20 में खाता नहीं खुला. वहीं शेफाली ने भी सिर्फ 2 रन बनाए. दूसरे T20 में स्मृति ने 32 रन बनाए तो शेफाली ने 22 रन की पारी खेली. जबकि तीसरे और आखिरी T20 में स्मृति एक बार फिर से दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाई और सिर्फ 8 रन बनाए. वहीं शेफाली ने 11 रन बनाए.

स्मृति-शेफाली ने T20 सीरीज में 50 रन भी नहीं बनाए

स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा का प्रदर्शन इतना खराब रहा है, इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में ओवरऑल रन बनाने वालों की टॉप-5 लिस्ट में भी दोनों में से कोई नहीं हैं. सीरीज के 3 मैचों में दोनों के लिए 50 रन भी जोड़ पाना मुश्किल हो गया. स्मृति मंधाना ने T20 सीरीज के 3 मैचों में 13.33 की औसत से 40 रन बनाए तो वहीं शेफाली वर्मा ने 11.66 की औसत से 35 रन बनाए हैं.

स्मृति-शेफाली की परेशानी, टीम इंडिया की मुश्किल

महिला T20 वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पर जीत दर्ज करने के लिए बेहतर शुरुआत का मिलना बहुत जरूरी होता है. भारतीय टीम के लिए वो काम स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा को करना है. लेकिन, जिस तरह की दोनों की मौजूदा फॉर्म है, उसने टीम इंडिया की मुश्किल को बढ़ा दिया है. स्मृति और शेफाली वैसे बड़े मैचों के खिलाड़ी रहे हैं. ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि ये दोनों T20 वर्ल्ड कप में अपने पुराने रंग में दिखेंगे.

न्यूज़ीलैंड ने टीम इंडिया के खिलाफ शेड्यूल का किया ऐलान, 7 साल में पहली बार होगा ऐसा

न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया के खिलाफ शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. इस साल अक्टूबर में भारतीय टीम न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहां उसे 40 दिन में 12 मैच खेलने हैं. इन 12 मुकाबलों में 5 T20, 5 वनडे और 2 टेस्ट खेले जाने हैं. इस दौरे की शुरुआत 22 अक्टूबर से T20 सीरीज के साथ होगी. जबकि इसका अंत 27 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले के साथ होगा. ICC वेबसाइट के मुताबिक न्यूजीलैंड ने इससे पहले कभी 12 मैचों की सीरीज की मेजबानी नहीं की.

7 सालों में पहली बार होगा ऐसा

टीम इंडिया का बीते 7 सालों में ये पहला न्यूजीलैंड दौरा होगा, जिस पर वो टेस्ट मैच भी खेलती दिखेगी. आखिरी बार टेस्ट सीरीज खेलने के इरादे से टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड का दौरान साल 2019 में किया था. न्यूजीलैंड में लिमिटेड ओवर सीरीज भारतीय टीम साल 2022 के बाद खेलती दिखेगी.

22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक T20 सीरीज : टीम इंडिया का न्यूजीलैंड दौरा T20 सीरीज के साथ शुरू होगा. T20 सीरीज के पहले दो मुकाबले क्राइस्टचर्च में 22 और 24 अक्टूबर को खेले जाएंगे. तीसरा T20 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में होगा. जबकि चौथा T20 ऑकलैंड में 30 अक्टूबर को खेला जाएगा. वहीं 5वां और आखिरी T20 मुकाबला 1 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा.

4 नवंबर से 15 नवंबर तक वनडे सीरीज

4 नवंबर को वनडे सीरीज का पहला मैच ऑकलैंड में खेला जाएगा. वहीं दूसरा वनडे वेलिंगटन में 7 नवंबर को जबकि तीसरा वनडे 10 नवंबर को हैमिलटन में खेला जाएगा. वनडे सीरीज के आखिरी दो मुकाबले माउंट माउंगनेई में 13 और 15 नवंबर को खेले जाएंगे।

19 नवंबर से टेस्ट सीरीज

वनडे सीरीज के खत्म होने के 3 दिन बाद ही टेस्ट सीरीज का आयोजन होगा. टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 19 से 23 नवंबर के बीच वेलिंगटन में खेला जाएगा. वहीं आखिरी टेस्ट 27 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा.

भारत का न्यूजीलैंड दौरा पूरे 40 दिन का होगा, जिस पर 12 मुकाबले खेले जाने हैं. 4 साल के अंतराल पर हो रहे इस दौरे पर भारतीय टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद उनके फैंस को रहेगी.

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच की टीम इंडिया ऐसे कर रही तैयारी, दूसरी बार होगा ऐसा

आईपीएल 2026 के खत्म होने के बाद अब निगाहें भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले टेस्ट मैच पर जम गई है. दोनों देशों के बीच इकलौता टेस्ट 6 जून से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले की तैयारी में टीम इंडिया पूरे जोर शोर से लगी है.

भारतीय टीम की तैयारियों का पहला वीडियो सामने आया है, जिसमें आप भारतीय क्रिकेटरों को T20 वाला अपना गियर बदलकर टेस्ट फॉर्मेट मोड ऑन करते देख सकते हैं.

टीम इंडिया की प्रैक्टिस में क्या-क्या हुआ?

BCCI ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया का पहला वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो की शुरुआत टीम इंडिया की फील्डिंग ड्रील के साथ होती है. उसके बाद बल्लेबाजों की बल्लेबाजी का अभ्यास नजर आता है. नेट्स पर केएल राहुल को कुलदीप यादव और दूसरे भारतीय स्पिनर के सामने अपनी बल्लेबाजी को परखते देखा जा सकता है. राहुल के अलावा यशस्वी जायसवाल भी रेड बॉल के सामने खुद को तैयार करते दिख रहे हैं. वीडियो के आखिर में गौतम गंभीर की भी झलक है जो कि भारतीय खिलाड़ियों की मेहनत पर बाज सी नजरें जमाए दिख रहे हैं.

दूसरी बार होगा ऐसा

भारत और अफगानिस्तान के लिए ये दूसरा मौका होगा, जब वो दोनों टेस्ट क्रिकेट में आमने-सामने होंगे. पहली बार दोनों टीमें साल 2018 में बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी मैदान पर आमने-सामने हुई थीं, जिसमें भारत ने पारी और 262 रन के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी.

प्रशासनिक लापरवाही से कपूरथला रोड पर लगा लंबा जाम, घंटों बहता रहा पीने का पानी

» प्रथम न्यूज । जालंधर
03 जून (मनू रहेजा)

बस्ती बावा खेल क्षेत्र में गैस पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्य के दौरान हुई लापरवाही के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।जानकारी के अनुसार, कार्य के दौरान मजदूरों से मुख्य पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे पीने का पानी घंटों तक सड़क पर व्यर्थ बहता रहा। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि संबंधित विभागों और प्रशासन की ओर से समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते समस्या और गंभीर हो गई।

पानी की पाइपलाइन टूटने के कारण सड़क पर जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे कपूरथला रोड पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। कड़कड़ाती धूप में वाहन चालकों को लंबी कतारों में रेंगते हुए सफर करना पड़ा और लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा।

स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले चार दिनों से गुरुद्वारे को जाने वाला प्रमुख मार्ग भी बंद पड़ा हुआ है, जिससे श्रद्धालुओं और आसपास के निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा।

स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब पाइपलाइन की मरम्मत के दौरान एक बिजली का खंभा भी क्षतिग्रस्त हो गया। खंभा टूटने से हाई-वोल्टेज बिजली की तारें सड़क पर गिर गईं, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक को काफी देर तक रोकना पड़ा। घटना के कारण क्षेत्र में भय और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।स्थानीय निवासियों ने प्रशासन, नगर निगम, जल आपूर्ति विभाग और संबंधित गैस पाइपलाइन कंपनी के अधिकारियों से मांग की है कि मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि कार्य शुरू करने से पहले संबंधित विभागों के साथ उचित समन्वय किया जाता, तो पानी की पाइपलाइन और बिजली व्यवस्था को नुकसान से बचाया जा सकता था। लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द सड़क और अन्य सुविधाओं को सामान्य करने की मांग की है।

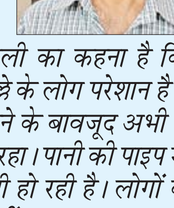

हैदर अली का कहना है कि 4 दिन से मोहल्ले के लोग परेशान है। प्रशासन को कहने के बावजूद अभी तक काम नहीं हो रहा। पानी की पाइप में लीकेज अभी भी हो रही है। लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा

कमलदीप सिंह गुंबर का कहना है कि कंपनी की वजह से सारा मोहल्ला निवासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को बार बार बोलने के बावजूद सोया हुआ है। गैस पाइपलाइन डालने वाली कंपनी के कर्मचारी भी भाग गए हैं। इनका कहना है कि पानी बहने के कारण इसकी बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंच रहा है

केवल सिंह ढिल्लों की ताजपोशी से पंजाब भाजपा को मिलेगी नई दिशा : संजीव खन्ना

जीरकपुर, 3 जून (सुखविन्दर सिंह) पंजाब भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में केवल सिंह ढिल्लों की आज हुई ताजपोशी को ऐतिहासिक दिन बताते हुए भाजपा के प्रदेश सचिव एवं डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी संजीव खन्ना ने कहा कि उनकी अगुवाई में पार्टी को पूरे प्रदेश में नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि केवल सिंह ढिल्लों एक अनुभवी, जनसरोकारों से जुड़े और मजबूत संगठनात्मक क्षमता वाले नेता हैं। उनके नेतृत्व में भाजपा का जनाधार और अधिक मजबूत होगा।

संजीव खन्ना ने कहा कि आज की ताजपोशी केवल एक संगठनात्मक परिवर्तन नहीं, बल्कि पंजाब भाजपा के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में इस फैसले को लेकर भारी उत्साह है और प्रदेश के हर क्षेत्र में भाजपा को मजबूत करने के लिए नए जोश और समर्पण के साथ कार्य किया जाएगा।

खन्ना ने कहा कि पंजाब इस समय कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है और जनता एक मजबूत तथा विकासोन्मुखी विकल्प की तलाश में है। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा आने वाले समय में लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी।

उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य लक्ष्य बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना, युवाओं को पार्टी से जोड़ना और जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाना होगा। उनके अनुसार केवल सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में भाजपा पंजाब के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाएगी तथा विकास, पारदर्शिता और सुशासन के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी।

संजीव खन्ना ने कहा कि आज की ताजपोशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर दिया है और यही जोश आने वाले समय में भाजपा को पंजाब की राजनीति में और अधिक मजबूत स्थिति प्रदान करेगा।

एक नज़र

RBI ने सोना बेचने की खबरों को बताया गलत, कहा- देश के पास अब भी 880.52 टन गोल्ड रिजर्व सुरक्षित

नई दिल्ली (ब्यूरो) : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को उन मीडिया रिपोर्टों को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि केंद्रीय बैंक ने अपने स्वर्ण भंडार (गोल्ड रिजर्व) का एक हिस्सा बेच दिया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि उसके पास मौजूद भौतिक सोने का भंडार पहले की तरह 880.52 टन ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आरबीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि रिजर्व बैंक ने सोना बेचा है, लेकिन यह जानकारी सही नहीं है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसके स्वर्ण भंडार से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से मासिक बुलेटिन में प्रकाशित की जाती है और वर्तमान में भौतिक सोने का स्टॉक 880.52 टन पर स्थिर बना हुआ है।

आरबीआई ने कहा कि उसके स्वर्ण भंडार का पूरा विवरण मासिक बुलेटिन में उपलब्ध रहता है, जिसे कोई भी व्यक्ति आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकता है। बैंक ने दोहराया कि अभी तक सोने के भौतिक भंडार में कोई कमी नहीं आई है। केंद्रीय बैंक ने लोगों से अपील की कि वे इस तरह की खबरों पर भरोसा करने के बजाय आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली आधिकारिक जानकारी को ही सही मानें। इस मामले पर प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट चेक यूनिट ने भी स्पष्टीकरण जारी किया। पीआईबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि आरबीआई ने लगभग 12 अरब डॉलर मूल्य का सोना बेच दिया है, जबकि यह दावा पूरी तरह फर्जी है। पीआईबी के अनुसार, आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। सितंबर 2025 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 13.92 प्रतिशत थी, जो 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 16.70 प्रतिशत हो गई। इसके बाद 22 मई 2026 तक यह और बढ़कर 16.85 प्रतिशत पहुंच गई। दरअसल, इससे पहले एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग का हवाला देते हुए दावा किया गया था कि आरबीआई ने 22 मई तक के दो सप्ताह के दौरान लगभग 12 अरब डॉलर मूल्य का सोना बेचकर विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां खरीदी हो सकती हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बाजार में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। हालांकि आरबीआई और पीआईबी दोनों ने इन दावों को गलत बताते हुए साफ कर दिया है कि भारत के स्वर्ण भंडार में कोई कमी नहीं आई है और देश के पास मौजूद 880.52 टन सोना पूरी तरह सुरक्षित है।

विश्व साइकिल दिवस पर चंडीगढ़ प्रशासन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों व कर्मचारियों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

चंडीगढ़, 3 जून (पुनीत महाजन)- विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज चंडीगढ़ प्रशासन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ जीवनशैली तथा सतत परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साइकिल, पैदल एवं सार्वजनिक बसों के माध्यम से अपने कार्यालय पहुंचकर एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समय-समय पर दिए गए पर्यावरण संरक्षण, फिट इंडिया और स्वच्छ भारत के संदेशों से प्रेरित होकर चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस दौरान कई अधिकारी साइकिल से, कुछ पैदल तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी सार्वजनिक बसों से कार्यालय पहुंचे।

इस अवसर पर चीफ इंजीनियर सी.बी. ओझा, चीफ आर्किटेक्ट राजीव मेहता, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जिगना के. सिंघाडिनिया, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर संदीप कुमार, डिवीजन नंबर-5 , एसडीओ विपिन कुमार डिवीजन नंबर-6 , एसडीओ सुमित दीक्षित ,राकेश कुमार, सुपरिंटेंडेंट तथा प्रोग्रामर गुरप्रीत सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

अधिकारियों ने कहा कि साइकिल और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग न केवल प्रदूषण को कम करने में सहायक है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ वातावरण के निर्माण के लिए अधिक से अधिक साइकिल एवं सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ प्रशासन की यह पहल समाज में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने तथा स्वस्थ जीवनशैली को अपनाने के लिए प्रेरणादायक संदेश देने वाली रही।

शारीरिक शोषण की शिकायत से नाराज कामांध युवक ने उन्नाव में हत्या कर बुलंदशहर में फेंकी लाश

कानपुर (सुनील बाजपेई)- शरीर की आग बुझाने यानी वासना में अंधे कामांध युवक ने बहाने से बुलाकर कानपुर में रहने वाली युवती की उन्नाव में गोली मारकर हत्या कर दी। इस युवती ने 19 मई को सदर कोतवाली में नर्सिंगहोम संचालक के खिलाफ शारीरिक शोषण करने की शिकायत की थी। जिससे हत्यारा युवक बहुत-बहुत नाराज था। उसका अपहरण उसके निवास क्षेत्र बर्रा से किया गया था । इसके बाद उसके शव को बुलंदशहर जाकर फेंक दिया। मामले युवती की मां ने उन्नाव के नर्सिंगहोम संचालक और उसके भतीजे के खिलाफ अपहरण कर हत्या की आशंका जताते हुए मुकदमा कराया था। फिलहाल जांच में जुटी पुलिस आरोपित भतीजे को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उन्हें हत्या कबूल कर ली और दबाव बनने पर नर्सिंगहोम संचालक ने भी थाने में सरेंडर कर दिया। वहीं, शव की बरामदगी के लिए आरोपित भतीजे को लेकर पुलिस एक टीम बुलंदशहर को रवाना हो गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मूलरूप से उन्नाव की रहने वाली महिला बच्चों की पढ़ाई के लिए बी-ब्लाक कर्रही विश्वबैंक बर्रा में किराए का कमरा लेकर रहती है। 25 मई को उन्होंने बर्रा थाने में उन्नाव के शेखपुर स्थित उत्तम हास्पिटल के संचालक देवकांत उत्तम और उसके रिश्ते में भतीजे व एंबुलेंस चालक विवेक पटेल के खिलाफ मुकदमा कराया था। इसके बाद ही अपरण करके इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में गहनता से जुटी है।

HCS मनीष कुमार लोहान को मिली दो और बड़ी जिम्मेदारियां, अब संभालेंगे तीन विभागों का कार्यभार

चंडीगढ़ (एएम नाथ)- हरियाणा सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 2013 बैच के HCS अधिकारी मनीष कुमार लोहान को दो अतिरिक्त महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार मनीष कुमार लोहान को सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें खान एवं भू-विज्ञान विभाग के अतिरिक्त निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। मनीष कुमार लोहान वर्तमान में हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। नए आदेशों के बाद अब वह एक साथ तीन महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभालेंगे। सरकार ने उन्हें उनके वर्तमान दायित्वों के साथ इन दोनों विभागों की जिम्मेदारी भी दी है। सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों को जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है, जबकि खान एवं भू-विज्ञान विभाग खनिज संसाधनों के प्रबंधन और नियमन से जुड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। ऐसे में इन दोनों विभागों की जिम्मेदारी मनीष कुमार लोहान को सौंपे जाने को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस नियुक्ति से यह संकेत मिलता है कि हरियाणा सरकार प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए अनुभवी HCS अधिकारियों पर अधिक भरोसा जता रही है। साथ ही, हरियाणा सिविल सेवा अधिकारियों की जिम्मेदारियों और भूमिका में लगातार विस्तार भी देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रूसी तेल खरीद पर छूट खत्म करेगा अमेरिका!

कच्चे तेल की सप्लाई पर मंडरा सकता है संकट

» प्रथम न्यूज । नई दिल्ली
03 जून (एजेंसी)

रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदने वाले भारत के लिए आने वाले दिनों में नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिया है कि वाशिंगटन रूसी तेल खरीद पर दी गई छूट (सैंक्शंस वेवर) को लंबे समय तक जारी रखने के पक्ष में नहीं है और इसे जल्द समाप्त करना चाहता है।

अमेरिकी सीनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी की सुनवाई के दौरान रुबियो ने कहा कि रूसी तेल पर प्रतिबंध अमेरिकी नीति का हिस्सा है और मौजूदा छूट केवल एक अस्थायी व्यवस्था है। उन्होंने कहा, हम इस छूट को जितनी जल्दी संभव हो समाप्त करना चाहते हैं। इसे वैश्विक तेल आपूर्ति बनाए रखने के लिए दिया गया था।

मौजूदा वेवर 17 जून को समाप्त होने वाला है। यह छूट पहली बार मार्च में लागू की गई थी और बाद में दो बार बढ़ाई गई। यूक्रेन युद्ध और ईरान से जुड़े क्षेत्रीय तनावों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने यह कदम उठाया था।

भारत इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस ने भारी छूट पर कच्चा तेल बेचना शुरू किया, जिससे भारत दुनिया के प्रमुख खरीदारों में शामिल हो गया। इससे देश को कम कीमत पर ऊर्जा उपलब्ध हुई और घरेलू अर्थव्यवस्था को भी राहत मिली।

रुबियो ने स्वीकार किया कि इस छूट का लाभ केवल भारत को ही नहीं, बल्कि कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं को भी मिला है। उनके अनुसार, रूसी तेल की आपूर्ति ने वैश्विक बाजार में कीमतों को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि अमेरिका का लंबे समय से यह तर्क रहा है कि रूस के तेल निर्यात से मिलने वाला राजस्व यूक्रेन युद्ध को वित्तीय समर्थन देता है। इसी वजह से वाशिंगटन चाहता है कि भारत समेत बड़े आयातक देश धीरे-धीरे रूसी तेल पर अपनी निर्भरता कम करें।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। अमेरिका का आरोप था कि भारत रूसी तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से मॉस्को को आर्थिक सहायता पहुंचा रहा है। हालांकि बाद में दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के तहत इस अतिरिक्त टैरिफ को वापस लेने का निर्णय लिया गया। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक फैक्ट शीट में दावा किया गया था कि भारत ने रूसी तेल के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात को रोकने की प्रतिबद्धता जताई है।

हालांकि भारत सरकार ने सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी भी प्रतिबद्धता की पुष्टि नहीं की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका भविष्य में प्रतिबंधों को लेकर नरम रुख अपनाता है, तो भारत को फिर से सस्ते रूसी तेल का लाभ मिल सकता है। वहीं, यदि छूट समाप्त होती है तो भारत को वेनेजुएला, पश्चिम एशिया और अफ्रीकी देशों जैसे वैकल्पिक स्रोतों से तेल आयात बढ़ाने की रणनीति अपनानी पड़ सकती है।

जैन मंदिर में चोरी तीन और संदिग्ध गिरफ्तार

» प्रथम न्यूज । मध्य प्रदेश
03 जून (ब्यूरो)

एरोड्रम इलाके में स्थित ग्रेटर बाबा मंदिर कॉम्प्लेक्स के श्री दिगंबर जैन नवग्रह जिनालय में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने मंगलवार को तीन और संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तारीयों के बाद इस मामले में कुल सात संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं। पुलिस के अनुसार, कुछ दिन पहले मंदिर में चोरी की घटना हुई थी, जिसके तुरंत बाद चार लोगों को गिरफ्तार किया गया और चोरी का कुछ सामान बरामद किया गया। मंगलवार की गिरफ्तारी उन चार संदिग्धों के साथियों से हुई। एक टिप-ऑफ पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सोमवार को धार रोड के पास इन तीन संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। सूत्रों के मुताबिक, संदिग्धों ने मोटरसाइकिल से भागने की कोशिश की, लेकिन सुपर कॉरिडोर सर्विस रोड पर तेज़ गति से भागते समय गिर गए। गिरने के बाद पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर मंदिर में हुई चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। गिरफ्तारियों के दौरान उनके पास चोरी की गई चांदी और अष्टधातु की चीज़ें भी मिलीं। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों की पहचान लखन मकवाना, दीपक और रामबाबू यादव के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि ये सभी आदतन अपराधी हैं और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में चोरी, डकैती और सेंधमारी से जुड़ा हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मंदिरों में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इन अपराधियों की गिरोहबंदी इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए विशेष टीमों को लगाया गया है।

भारत समेत 60 देशों पर नया टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका

» प्रथम न्यूज । वॉशिंगटन
03 जून (एजेंसी)

एक ओर अमेरिका भारत के साथ व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन भारत सहित कई देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ने भारत समेत 60 देशों के खिलाफ नया शुल्क लगाने का प्रस्ताव जारी किया है।

यूएसटीआर के अनुसार, इन देशों ने जबरन श्रम (Forced Labor) से निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। अमेरिकी व्यापार कानून 1974 की धारा 301 के तहत की गई समीक्षा में यह पाया गया कि इन देशों की कुछ नीतियां और कार्यप्रणालियां अमेरिकी व्यापार पर अनावश्यक बोझ डालती हैं और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती हैं।

यूएसटीआर, जो अमेरिकी विदेश व्यापार नीति तैयार करने वाली प्रमुख संघीय एजेंसी है, ने कहा कि भारत समेत 54 देश ऐसे उत्पादों के निर्यात को रोकने में विफल रहे हैं, जिनके निर्माण में जबरन श्रम का इस्तेमाल होने की आशंका है। इस सूची में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बहरीन,

बांग्लादेश, चीन, जापान, सऊदी अरब, सिंगापुर, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी शामिल हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर ने कहा, हमारे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों द्वारा जबरन श्रम से निर्मित वस्तुओं के निर्यात को रोकने में विफल रहना स्वीकार्य नहीं है।

इससे अमेरिकी कामगारों और उद्योगों को असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। यूएसटीआर ने इन देशों पर 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है और इस संबंध में सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। एजेंसी का कहना है कि जबरन श्रम से जुड़े आयातों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं होने से वैश्विक स्तर पर ऐसे श्रम के उन्मूलन के प्रयास कमजोर पड़ते हैं।

यह प्रस्ताव ऐसे समय सामने आया है, जब भारत और अमेरिका के बीच एक संभावित व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, जिनमें बाजार पहुंच, शुल्क संरचना, डिजिटल व्यापार और कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है।

यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों और चल रही व्यापार वार्ताओं पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय से पहले अमेरिकी प्रशासन सार्वजनिक सुझावों और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रियाओं पर विचार करेगा।

आरबीआई की तीन दिवसीय एमपीसी बैठक आज से शुरू, महंगाई और आर्थिक वृद्धि पर रहेगी नजर

» प्रथम न्यूज । नई दिल्ली
03 जून (ब्यूरो)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक बुधवार से शुरू हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच केंद्रीय बैंक इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रवार को नीतिगत फैसलों की घोषणा करेंगे।

जून की मौद्रिक नीति समीक्षा ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव लगातार बना हुआ है और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इससे आर्थिक परिदृश्य और अधिक जटिल हो गया है। हालांकि, अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आरबीआई इस बार ब्याज दरों को स्थिर रख सकता है, लेकिन वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए उसके बयान का रुख पहले की तुलना में अधिक

सतर्क या सख्त हो सकता है। एचएसबीसी की मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी के अनुसार, निकट भविष्य में आरबीआई ब्याज दरों को स्थिर रखने की नीति अपना सकता है, लेकिन समय के साथ कुछ सख्ती की संभावना भी बन सकती है। उन्होंने कहा कि बाजार फिलहाल 2026 की चौथी तिमाही से लगभग दो बार ब्याज दरों में कटौती की संभावना देख रहा है, न कि किसी बड़े स्तर की सख्ती की। भंडारी के मुताबिक, आरबीआई के संशोधित आर्थिक अनुमानों पर विशेष ध्यान रहेगा, खासकर इस बात पर कि वह ऊर्जा क्षेत्र में जारी झटकों का आकलन कैसे करता है और क्या वह कच्चे तेल की औसत कीमत का अपना अनुमान पहले के लगभग 85 डॉलर प्रति बैरल से बढ़ाता है या नहीं।

खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग गार्ड की पिटाई; तीन लोग गिरफ्तार

» प्रथम न्यूज । पटना
03 जून (ब्यूरो)

बिहार की राजधानी पटना में चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ और गार्ड के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद भी शामिल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग भी हुई है।

पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक, मंगलवार की रात में करीब 10:10 बजे कदमकुंआ थानांतर्गत खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर कुछ लोगों द्वारा पथराव एवं तोड़फोड़ किए जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई।

घटनास्थल पर आसपास के लोगों से पूछताछ करने एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को देखने के बाद पुलिस को यह जानकारी मिली कि पास के ही ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान से जुड़े 15 से 20 लोगों द्वारा पथराव एवं तोड़फोड़ किया गया है। पुलिस ने साफ कर दिया कि सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद स्पष्ट है कि फायरिंग नहीं की गई है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना के दौरान कोचिंग में कार्यरत गार्ड के साथ मारपीट भी की गई थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस संबंध में खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग के एक कर्मचारी द्वारा एक प्राथमिकी संबंधित थाना में दर्ज कराई गई है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद और तोड़फोड़ में पहचाने गए अभिषेक और गौरव की गिरफ्तारी की है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस मामले में शामिल अन्य चार-पांच लोगों की भी पहचान कर ली गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

इससे पहले भी खान सर के कोचिंग पर 10 मई 2019 को भी निशाना बनाकर देसी बम से हमला किया गया था।

उस समय सुबह करीब 10 बजे कदमकुआं थाना क्षेत्र के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान जीएस रिसर्च सेंटर के बाहर अज्ञात बदमाशों ने लगातार दो देसी बम फेंके थे।

पंजाब में निहंगों ने लगाया 'खालसा राज टैक्स', हिमाचल से आने वाली गाड़ियों से की जा रही वसूली

» प्रथम न्यूज । चंडीगढ
03 जून (ब्यूरो)

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वसूले जा रहे एंट्री टैक्स के विरोध ने अब नया रूप ले लिया है। पंजाब में निहंग संगठनों ने इसके जवाब में बुधवार से 'खालसा टैक्स' की वसूली शुरू कर दी है। कुल्लू-मनाली हाईवे पर कीरतपुर साहिब में मोड़ा टोल प्लाजा के निकट हिमाचल प्रदेश से आने वाले वाहनों से खालसा राज टैक्स के नाम पर स्वैच्छिक राशि एकत्रित की जा रही है।

इस अभियान की अगुआई तरना दल के निहंग कर रहे हैं। तरना दल के प्रतिनिधि निहंग अच्छर सिंह के अनुसार कारों और अन्य छोटे वाहनों से 100 रुपये, हल्के व्यावसायिक वाहनों से 200 रुपये तथा बड़े वाहनों से 300 से 500 रुपये तक लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोपहर बाद गांव मोड़ा के निकट सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा।

सरबत के भले' के लिए होगा उपयोग

इस वसूली को गैरकानूनी बताए जाने के सवाल पर निहंग नेताओं ने कहा कि यह राशि किसी निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि 'सरबत के भले' और सामाजिक कार्यों के लिए खर्च की जाएगी।

उनका कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए टोल वसूलता है, लेकिन हिमाचल सरकार द्वारा लिया जा रहा एंट्री टैक्स लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ है।निहंग नेताओं ने पंजाब और हिमाचल सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनके आंदोलन को रोकने का प्रयास किया गया तो वे और बड़े स्तर पर संघर्ष छेड़ने के लिए तैयार हैं।

क्या है हिमाचल एंट्री टैक्स विवाद?

सीएम सुक्खू के हस्तक्षेप के बाद राहत

विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हस्तक्षेप करना पड़ा। 31 मार्च 2026 को सरकार ने निजी कारों और कुछ यात्री वाहनों पर प्रस्तावित बढ़ोतरी वापस लेने की घोषणा की। हालांकि संशोधित दरें पूरी तरह समाप्त नहीं की गईं। वर्तमान में कार, जीप और वैन पर 100 रुपये, 6 से 12 सीट वाले वाहनों पर 130 रुपये, ट्रैक्टर पर 100 रुपये तथा भारी वाहनों पर 800 रुपये तक एंट्री टैक्स वसूला जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों से एंट्री टैक्स वसूलने की व्यवस्था कोई नई नहीं है। यह प्रावधान वर्ष 1975 में लागू किए गए हिमाचल प्रदेश टोल्स एक्ट के तहत अस्तित्व में आया था। राज्य सरकार का तर्क है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के रखरखाव और विकास के लिए अतिरिक्त राजस्व की आवश्यकता होती है।

2025 में पहली बढ़ोतरी

अप्रैल 2025 में हिमाचल सरकार ने एंट्री टैक्स दरों में संशोधन किया था। उस समय निजी और व्यावसायिक वाहनों पर 10 से 20 रुपये तक की वृद्धि की गई थी। इसके तहत कार, जीप और वैन पर 70 रुपये, 6 से 12 सीट वाले वाहनों पर 110 रुपये, ट्रैक्टर पर 70 रुपये तथा भारी वाहनों पर 720 रुपये तक शुल्क निर्धारित किया गया था।

2026 में बढ़ा विवाद

फरवरी 2026 में नई टोल नीति के तहत कई श्रेणियों के वाहनों पर शुल्क में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया गया। निजी कारों और जीपों पर टैक्स 70 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये तक करने की योजना बनाई गई, जबकि अन्य व्यावसायिक वाहनों पर भी शुल्क बढ़ाया गया।

इस फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में ट्रांसपोर्टरों, व्यापारिक संगठनों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। दोनों राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक और मालवाहक वाहन हिमाचल जाते हैं, इसलिए इसका सीधा असर इन क्षेत्रों पर पड़ता था।

राजनीतिक और सामाजिक बहस जारी

एंट्री टैक्स को लेकर हिमाचल और पड़ोसी राज्यों के बीच बहस अभी भी जारी है। जहां हिमाचल सरकार इसे राजस्व और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जरूरी बता रही है, वहीं विरोधी पक्ष इसे पर्यटकों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों पर अतिरिक्त बोझ करार दे रहा है।

अब पंजाब में 'खालसा टैक्स' की शुरुआत ने इस विवाद को नया राजनीतिक और सामाजिक आयाम दे दिया है।